रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 7, 1985/भाद्र 16, 1907
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1985/BHADRA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली 13 अगस्त, 1985

सूचनाएं

का०आ० 4089.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी० पी० घोष, पालिसिटर एण्ड एडवोकेट, 1 डाक्टर्स लेन, गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उन्हें दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं०एफ० 5(19)/85 -न्या.]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
New Delhi, the 13th August, 1985
NOTICES

S.O. 4089.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri B. P. Ghosh, Solicitor and Advocate, 1, Doctor's Lane, Gole Market, New Delhi-110001, for appointment as a Notary to practise in Union Territory of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(9)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

का०आ० 4090.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अधिनाथ गंगुली, अधिवक्ता 1 दो, गली पुराना डाकखाना-पहली मंजिल, कमरा नं० 7 (पाईन एन्ड पाईन) कलकत्ता-700001 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के

नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे कलकत्ता में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० फा० 5/37/85-न्या०]
एस० गुप्तु, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 16th August, 1985

S.O. 4090.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, unnder rule 4 of the said Rules, by Shri Adinath Ganguly Advocate, 1B, Old Post Office Street, 1st Floor, Room No. 7 (Pyne & Pyne), Calcutta-700001, for appointment as a Notary to practise in Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(37)/85-Judl.]
S. GOOPTU, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(गृह विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1985

का०आ० 4091.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एस० डी० ओ० (सिविल) (देहात), शिमला को उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त, मुआवजा पूल के भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना, शिमला, सोलन, किन्नौर, सिरमौर और बिलासपुर जिलों से संबंधित बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

इससे दिनांक 3 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या 3(2)/श्रम व पुनर्वास/67 का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(19) वि०सं०/84-एस० एस० II (ए)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Home Affairs)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 2nd August, 1985

S.O. 4091.—In exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints S.D.O. (Civil) (Rural), Shimla as Settlement Officer in respect of Una, Shimla, Solan, Kinnaur, Sirmaur & Bilaspur Distts of Himachal Pradesh for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to the Settlement Officer by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the compensation pool.

This supersedes Notification No. 3(2)/L&R/67 dated 3rd July, 1971.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(A)]

का०आ० 4092 विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एस०डी० ओ० (सिविल) कांगड़ा और नायब तहसीलदार (बिक्री) कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को, उनके अपने कार्य-भार के अतिरिक्त मुआवजा पूल के भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त अधिकारी और प्रबन्ध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए कांगड़ा जिला (ऊना तहसील को छोड़कर) कुल्लू, लाहौल और स्पीती, चम्बा और मंडी जिले के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी और प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

इससे दिनांक 3 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या 3(2)/श्रम और पुनर्वास/67 का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(19)/वि०सं०/84-एस एस० II(बी)]

S.O. 4092.—In exercise of the powers conefrred by Subsection (i) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints S.D.O. (Civil) Kangra & Naib Tehsildar (Sales) Kangra in Himachal Pradesh as Settlement Officer and Managing Officer in respect of Kangra District (Excluding Una Tehsil), Kulu, Lahaul and Spiti, Chamba and Mandi Districts for the purpose of performing, in addition to his own duties, the function assigned in the Settlement Officer & Managing Officer by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the compensation pool.

This supersedes Notification No. 3(2)/L&R/67 dated 3rd July, 1971.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(B)]

का०आ० 4093: विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उप सचिव (राजस्व I), हिमाचल प्रदेश सरकार, सहायता तथा पुनर्वास विभाग को, उप सचिव के रूप में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य में "मुआवजा पूल" के भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधि-नियम द्वारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

इससे दिनांक 28 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 5(2)/75-वि०सं० /एस एस० II का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं. 1(19)/वि०सं०/84-एस०एस० II(सी)]

S.O. 4093.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Deputy Secretary (Revenue-1) to the Government of Himachal Pradesh, Relief and Rehabilitation Department as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties, as Deputy Secretary the function assigned to such Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the lands and properties forming part of the "Compensation pool" within the State of Himachal Pradesh.

The supersedes Notification No. 5(2)/75-Spl. Cell/SS.II dated 28th July, 1975.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(C)]

का० आ० 4094.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उप-सचिव (चयन ग्रेड) (राजस्व II), हिमाचल प्रदेश सरकार, सहायता तथा पुनर्वास विभाग को, उप-सचिव के रूप में उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य में "मुआवजा पूल" भाग की भूमि और सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

इससे दिनांक 28 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या-5(2)/75-वि०सै० /एस० एस० II का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं. 1(19)/वि०सै० /84-एस०एस II(ई)]

S.O. 4094.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Deputy Secretary (Selection Grade) (Revenue-II) to the Govt. of Himachal Pradesh, R&R Department as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Deputy Secretary the function assigned to such Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the "Compensation Pool" within the State of Himachal Pradesh.

This supersedes Notification No. 5(2)/75-Spl. Cell/SS.II dated 28th July, 1975.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(E)]

का० आ० 4095.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सचिव, सहायता तथा पुनर्वास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को सचिव के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उप महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निपटान करने के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से उप महाभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं० 1(19)/वि०सं०/84-एस०एस० II (एफ)]
डी०डी०इंगटी, अवर सचिव

S.O. 4095.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) the Central Government hereby appoints, with immediate effect, Secretary, R&R Department, Government of Himachal Pradesh to be the Deputy Custodian General of Evacuee Property in addition to his own duties, as Secretary for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act,

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(F)]
D. D. INGTY, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1985

का.आ० 4096.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस विभाग की दिनांक 2-8-85 की अधिसूचना संख्या 1(19)/वि०सै./85-एस० स० II(सी) द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को शक्तियों का प्रयोग कर रहे उप सचिव, राजस्व I, हिमाचल प्रदेश सरकार, सहायता और पुनर्वास विभाग को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :—

1. उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की शक्तियां ।
2. उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण सुनने की शक्तियां ।
3. उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां ।

2. इससे 28 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 5/2/75-वि. सै०/एस०एस II का अधिक्रम किया जाता है ।

[सं० 1(19)/वि०सै०/84-एस०एस० II(डी०)]

New Delhi, the 14th August, 1985

S.O 4069.—In exercise of the powers conferred by Subsection (2) of Section (34) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) I hereby delegate to Deputy Secretary, (Rev.-I), to the Government of Himachal Pradesh, R&R Department, appointed as Settlement Comissioner vide this Department's Notification No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(C) dated 2nd August, 1985 the following powers of the C.S.C. :—

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.

(ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.

(iii) Powers to transfer cases under Section 28 of the said Act.

2. This supersedes Notification No. 5/2/75-Spl. Cell/SS.II dated 28th July, 1975.

[No 1(19)/Spl. Cell/84-SS. II(D)]

का० आ० 4097.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा महाभिरक्षक के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1 (19)/वि०सै०/84-एस एस० II (एफ) दिनांक 2 अगस्त, 1985 के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए उप महाभिरक्षक,

निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त सहायता तथा पुनर्वास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव को महाभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :—

1. अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।

2. अधिनियम की धारा 10(2)(O) के अधीन किसी भी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमोदन की शक्तियां।

3. निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 30-क के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां।

[सं 1(19)/वि०सै०/84-एस०एस० II (जी)]
जी० पा० एस० साहा, महाभिरक्षक

S.O. 4097.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to Secretary, Relief & Rehabilitation Department, Government of Himachal Pradesh, appointed as Deputy Costodian General of Evacuee Property for the State of Himachal Pradesh vide this Department's Notification No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(F) dated the 2nd August, 1985, the following powers of the Custodian General :—

(i) Powers under Sections 24 and 27 of the Act.

(ii) Powers of approval of transfer of any Evacuee Property under Section 10(2)(o) of the Act.

(iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950.

[No. 1(19)/Spl. Cell/84-SS.II(G)]
G. P. S. SAHI, Custodian General

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 1098.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 4 और धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन दंडनीय अपराध; और

(ख) ऊपर उल्लिखित अपराध, और वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनकी बाबत, प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र।

[संख्या 228/21/85-ए०वी०डी० II]

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMN. REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4098.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment namely :—

(a) Offences punishable under sub-sections (2) and (3) of section 3, section 4 and sub-section (4) of section 13 of the Terrorist and Disputive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985); and

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the offence mentioned above and any other offence committed in the source of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228|21|85-AVD.II]

का. आ. 4099.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध—

(ख) ऊपर उल्लिखित अपराध और वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनकी बाबत प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र।

[सं. 228/22/85-ए०वी०डी० II(i)]

S.O. 4099.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946, the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

(a) Offences punishable under section 34 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the offences mentioned above and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228|22|85-AVD-II(i)]

आदेश

का. आ. 4100.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार की सहमति से, पंजाब के संगरूर जिले के शेरपुर थाने में 20 अगस्त, 1985 को की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 98 के अधीन रजिस्टर किए गए मामले की बाबत, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराएं 302, 307 और 34, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25 और धारा 27 और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) की

धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराधों के, तथा वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित, प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का समस्त पंजाब राज्य पर विस्तार करती है।

[संख्या 228/22/85-ए. वी. डी. (II)(ii)]
एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4100.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Punjab, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Punjab for the investigation of offences punishable under sections 302, 307 and 34 of the Indian Panel Code, 1860 (45 of 1860), sections 25 and 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) and section 3 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, in regard to the case registered under FIR No. 98 dated 20th August, 1985 at Police Station Sherpur, District Sangrur, Punjab.

[No. 228/22/85-AVD.II(ii)]
M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1985

(आय-कर)

का.आ. 4101.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सोसाइटी ऑफ दि फ्रांसिसियन (हास्पिटलर) सिस्टर्स, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1985-86 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6323 (फा.सं. 197/40/83—आ.क.नि.-1)]
पी. सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th July, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4101.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Society of the Franciscan (Hospitaller) Sisters, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1985-86.

[No. 6323 (F. N. 197/40/83-ITI(AI)]
P. SAXENA, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1985

का. आ. 4102.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री डी. के. गुप्ता को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 29-6-85 से प्रारम्भ होकर 30-6-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी. के. गुप्ता अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ-2-8/82-आर आर बी.]
च. वा. मीरचन्दानी, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 12th August, 1985

S.O. 4102.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri D. K. Gupta as the Chairman of the Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad (MP) and specified the period commencing on the 29-6-85 and ending with the 30-6-88 as the period for which the said Shri D. K. Gupta shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-8/82-RRB]
C. W. MIRCANDANI, Director

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

का. आ. 4103.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध 31 दिसम्बर, 1985 तक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक इनका संबंध मैसर्स बंगाल हेल्थ एंड केमिकल वर्क्स लि. में गिरवीदार के रूप में 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10,050 शेयरों की शेयर धारिता से है।

[सं. 15/29/79-बी.ओ. III]
एम. के. कुट्टि, अवर सचिव

New Delhi, the 16th August, 1985

S.O. 4103.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a period upto the 31st December, 1985 in respect of its holding 10,050 shares of Rs. 10/- each in M/s Bengal Health and Chemical Works Ltd., as pledgee.

[No. 15/29/79-B.O. III]

का. आ. 4104.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की

उपधारा (2) के उपबंध यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता पर अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक इनका संबंध मैसर्स स्टार्लिंग फार्मास्यूटिकल्स प्राडक्ट्स कं. प्रा. लि. की शेयर शेयर धारिता से है ।

[सं. एफ-15/1/84-बी.ओ..3]
एम. के. एम. कुट्टि, अवर सचिव

S.O. 4104.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a period of two years from the date of the notification insofar as they relates to its holding of shares of M/s. Sterling Pharmaceutical Products Co Pvt. Ltd.

[No. 15/1/84 B.O. III]
M. K. M. KUTTY, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

आदेश

का. आ. 4105.—मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एवं पेपर लि., 16 व्हाईट रोड, मद्रास-600014 को 100 मिलियन डालर्स की विश्व बैंक ऋण के अधीन पूंजीगत माल आयात करने के लिए 1,18,80,200/- रुपए (एक करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार और दो सौ रुपए मात्र) के लिए आयात लाइसेंस सं. आई/सी/जी/2040450, दिनांक 8-7-1983 दिया गया था।

पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, मद्रास के पास पंजीकृत की गई थी और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के आंशिक रूप से 1,16,09, 715/- रुपए के मूल्य के लिए उपयोग में लाई गई थी।

2. अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक मद्रास के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. आई०/सी०जी०/2040450, दिनांक 8-7-1983 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति पार्टी द्वारा खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि., मद्रास को जारी की गई उक्त मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सं. आई/सी जी/2040450 दिनांक 8-7-1983 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सी जी II/आई डी/13/83-84/565]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 20th August, 1985

ORDER

S.O. 4105.—M/s. Tamil Nadu Newsprint & Paper Ltd., 16-White Road, Madras-600014 were granted an import licence No. I/CG/2040450 dated 8-7-83 for Rs. 1,18,80,200 (Rupees One Crore eighteen lahks eighty thousand and two hundred only) for import of capital goods under World Bank Loan of 100 million Dollars.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Madras Customs Authority and as the value of Customs purpose copy has utilised partly for Rs. 1,16,09,715/-.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Madras. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. I/CG/2040450 dated 8-7-83 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the power conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes copy No. I/CG/2040450 dated 8-7-83 issued to M/s. Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd., Madras is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/ID/13/83-84/565]

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

आदेश

का.आ. 4106.—श्री रतन के० हेमनानी, 713-रहेजा सेन्टर, नारीमन पाइंट, बम्बई-21 को आवेदक की स्वयं की विदेशी मुद्रा बचत के अधीन फ्रांस/आस्ट्रिया से संलग्न सूची के अनुसार बेकर बिस्कुटों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल मशीनरी के आयात के लिए 13,38,300/- रुपए (तेरह लाख अड़तीस हजार तीन सौ रुपए मात्र) (अमरीकी डालर 110878) के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2096846, दिनांक 22-11-1984 जारी किया गया था।

2. पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत किए और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. अपने तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका, 1985-88 के अध्याय दो के पैरा

86 में यथा अपेक्षित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2096846, दिनांक 22-11-1984 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सीसी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री रतन के हेमानी, बम्बई को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2096846, दिनांक 22-11-1984 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल नं. 1137/28/आई एन एस ए/84-85/सीजी-4]

पॉल बैक, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 22nd August, 1985

ORDER

S.O. 4106.—Shri Rattan K. Hemnani, 713, Raheja Centre Nariman Point, Bombay-21 was granted an import licence No. P/CG/2096846 dt. 22-11-84 for Rs. 13,38,300/- (Rupees Thirteen lakhs thirty eight thousand and three hundred only) (US $ 110878) for import of capital goods machinery for the manufacture of wafer Biscuits as per list attached from France/Austria under applicant's own foreign exchange saving abroad.

2. The party has applied for issue of Duplicate Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost/misplaced without having been registered with any Customs authority and not utilised at all.

3. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit as required in Para 86 of Chapter II of Hand Book of Import-Export Procedures 1985-88. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. P/CG/2094846 dt. 22-11-84 has been lost/misplaced by the party. In exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purpose copy of Import Licence No. P/CG/2096846 dt. 22-11-84 issued to Shri Rattan K. Hemnani, Bombay is hereby cancelled.

4. A duplicate Customs Purposes Copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 1137/28/INSA/84-85/CG IV]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports.

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1985

का.आ. 4107.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स ईस्टर्न कछार टी कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2298/85) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/115/85-एम-3]

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 19th August, 1985

S.O. 4107.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Eastern Cachar Tea Company Limited having its registered office at 9, Brabourne Road, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 2298/85).

[No. 16/115/85-M.III]

का. आ. 4108.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स ओरिएन्टल पावर केबल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, पी. ओ. कैबल नगर, स्टेन. अलनिया, जिला कोटा (राजस्थान) के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1239/76) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/18/83-एम.-3]

S.O. 4108.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Oriental Power Cables Limited having its registered office at PO. Cablenagar, Stn. Alnia, District Kota (Rajasthan) under the said Act (Certificate of Registration No. 1239/76).

[No. 16/18/83.M-III]

का.आ. 4109.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स आई.वी.पी. लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय शशीकान्त एन. रोडिजे मार्ग घोरूपदेव बम्बई-400033 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 964/74) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/14/85-एम०-3]

S.O. 4109.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. IVP Limited having its registered office at Shashikant N. Rodji Marg, Ghorupdeo, Bombay-400033 under the said Act (Certificate of Registration No. 964/74).

[No. 16/14/85-M.III]

का० आ० 4110.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स एलकोन (मद्रास) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 61/2

बी, इन्नौर हाई रोड, तिरुवोटीयूर, मद्रास-600019 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1485/80) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/23/85-एम०-3]

S.O. 4110.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Elecon (Madras) Limited having its registered office at 61|2B Ennore High Road, Tiruvotiyur Madras-600019 under the said Act (Certificate of Registration No. 1485|80).

[No. 16|23|85.M-III]

का०आ० 4111—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स एलकोन इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय आनन्द सोजित्रा रोड, वल्लभ विद्या नगर-388120 (गुजरात) के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1406/78) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/24/85-एम-3]

S.O. 4111.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Elecon Engineering Company Limited having its registered office at Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120 (Gujarat) under the said Act (Certificate of Registration No. 1406|78).

[No. 16|24|85.M-III]

का०आ० 4112—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स इमको एलकोन (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय आनन्द सोजित्रा रोड, वल्लभ विद्या-नगर-388120 (गुजरात) के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1429/78) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/25/85-एम-3]

S.O. 4112.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Emco Elecon (India) Limited having its registered office at Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120 (Gujarat) under the said Act (Certificate of Registration No. 1429|78).

[No. 16|25|85.M-III]

का०आ० 4113—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स मर्करी पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वीर सावरकार मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1353/77) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/27/84-एम-3]

S.O. 4113.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Mercury Paints and Varnishes Limited having its registered Office at Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-400025 under the said Act (Certificate of Registration No. 1353|77).

[No. 16/27/84-M-III]

का०आ० 4114—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स ब्लो प्लास्ट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वी०आई०पी० हाउस, 88-सी० ओल्ड प्रभादेवी रोड, बम्बई-400025 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण, (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2103/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/28/85-एम०-3]

S.O. 4114.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Blow Plast Limited having its registered office at VIP House, 88-C, Old Prabhadevi Road, Bombay-400025 under the said Act (Certificate of Registration No. 2103|84).

[No. 16|28|85-M-III]

का०आ० 4115—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स वी०आई०पी० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वी०आई०पी० हाउस, 88-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, बम्बई-400025 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2104/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/29/85-एम-3]

S.O. 4115.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. V.I.P. Industries Limited having its registered office at V.I.P. House, 88-C, Old Prabhadevi Road, Bombay-400025 under the said Act (Certificate of Registration No. 2104|84).

[No. 16|29|85.M-III]

का०आ० 4116—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स आर०बी० रोडा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 2, रेडक्रास प्लेस, पी०बा० नं० 2179, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजी-

रण प्रमाण-पत्र संख्या 1134/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/42/85-एम०-3]

S.O. 4116.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. R. B. Rodda & Company Limited having its registered office at 2, Red Cross Place P.B. No. 2179, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1134/75).

[No. 16/42/85.M-III]

का०आ० 4117.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिए पंजीकृत कार्यालय 2, रेड क्रोस प्लेस, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1045/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/43/85-एम०-3]

S.O. 4117.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Hindustan National Glass & Industries Limited having its registered office at 2, Red Cross Place, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1045/75).

[No. 16/43/85.M-III]

का०आ० 4118.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कनोरिया जूट काटन मिल्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4/1, रेड क्रोस प्लेस, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 1685/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/55/85-एम० 3]

S.O. 4118.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Kanoria Jute Cotton Mills Limited having its registered office 4/1, Red Cross Place, Calcutta-700001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1685/84).

[No. 16/55/85.M-III]

का०आ० 4119.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स एस एल एम-मानकलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वाधवानी मैनसन्स, दिनशा वाचा रोड, बम्बई-400020 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1715/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/56/85-एम०-3]

S.O. 4119.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. SLM-Maneklal Industries Limited having its registered office at Vaswani Mansion, Dinshaw Vachha Road, Bombay-400020 under the said Act (Certificate of Registration No. 1715/84).

[No. 16/56/85.M-III]

का०आ० 4120.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स इक्विपमेंट होसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वाधवानी मैनसन्स, दिनशा वाचा रोड, बम्बई-400020 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1710/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/57/85-एम०-3]

SO. 4120.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Equipment Hoses Limited having its Registered Office at Vaswani Mansions, Dinshaw Vachha Road, Bombay-400 020 under the said Act (Certificate of Registration No. 1710/84).

[No. 16/57/85.M-III]

का०आ० 4121.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स बेनिंगर-मानकलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वासवानी मैनसन्स, दिनशा वाचा रोड, बम्बई-400020 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1709/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/58/85-एम०-3]

S.O. 4121.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Benninger-Manekal Engineering Limited having its registered office at Vaswani Mansions, Dinshaw Vachha Road, Bombay-400 020 under the said Act (Certificate of Registration No. 1709/84).

[No. 16/58/85.M-III]

का०आ० 4122.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स मोरीस इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय भोसारी इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पूना-411026 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2329/85) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं० 16/62/85-एम०-3]

S.O. 4122.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Morris Eletronics Limited having its registered office at Bhosari Industrial

Estate, Poona-411026 under the said Act (Certificate of Registration No. 2329/85).

[No. 16/62/85.M-III]

का०आ० 4123.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कनोडिया एक्सपोर्टस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 8, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2299/85) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/73/85-एम०-3]

S.O. 4123.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Kanodia Exports Limited having its registered office at 8, Brabourne Road, Calcutta-700 001, under the said Act (Certificate of Registration No. 2299/85).

[No. 16/73/85-M.III]

का०आ० 4124.— एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स बंगाल टी एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-700001 के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2297/85) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/76/85-एम०-3]

S.O. 4124.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. Bengal Tea & Industries Limited having its registered office at 9, Brabourne Road, Calcutta-700 001 under the said Act (Certificate of Registration No. 2297/85).

[No. 16/76/85-M.III]

का. आ. 4125.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स सोमानी प्रोप्रटीज प्राइवेट लि. पंजीकृत कार्यालय 2, रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता— 700001 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 1136/75) से निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/ 110/ 85–एम.–3]

S.O. 4125.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Somany Properties Private Limited having its registered office at 2, Red Cross Place, Calcutta-700 001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1136/76).

[No. 16/110/85.M-III]

का. आ. 4126.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप–धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स वारेन टी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय देवहाल टी एस्टेट, पी. ओ. हुगरीजा जिला, डिब्रुगढ़, असम– 786601 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण– पत्र संख्या 1470/79) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/118/85–एम–3]

S.O. 4126.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Warren Tea Ltd. having its registered office at Deohall Tea Estate, P.O. Hoogrijan Distt. Dibrugarh, Assam-786 601 under the said Act (Certificate of Registration No. 1470/79).

[No. 16/118/85-M-III]

का. आ. 4127.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्– द्वारा मैसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय प्रोस्पेक्ट, चेम्बर्स 317/21, डा. दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट बम्बई– 400001 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण– पत्र संख्या 1526/81) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/121/85–एम–3]

S.O. 4127.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Dharamsi Morarji Chemical Company Limited having its registered office at Prospect Chambers, 317/21, Dr. Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Bombay-400001 under the said Act (Certificate of Registration No. 1526/81).

[No. 16/121/85-M-III]

का. आ. 4128.— एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसर्स शेषाशाई पेपर बोर्डस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय पाल्लीपलायम सलेम जिला– इरोड–638007 (तमिलनाडु) के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण– पत्र संख्या 500/70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/129/85–एम.–3]

S.O. 4128.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Seshasayee Paper and Boards Limited having its registered office at Pallipalayam, Salem District, Erode-638 007 (Tamilnadu) under the said Act (Certificate of Registration No. 500/70).

[No. 16/129/85.M-III]

का. आ. 4129.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्–

द्वारा मैसर्स ग्लास इक्युपमैन्ट (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 603–दीप शिखा, 8–राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली–110008 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण) (पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 1097/75) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/140/85–एम.–III]

S.O. 4129.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Glass Equipment (India) Limited having its registered office at 603-Deep Sikha, 8-Rajendra Place, New Delhi-110008 under the said Act (Certificate of Registration No. 1097/75).

[No. 16/140/85.M-III]

का. आ. 4130.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्–द्वारा मैसर्स सॉफ्टवेयर सर्विसेस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एस पी आई सी सेन्टर, 97– माउन्ट रोड मद्रास– 600032 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 1714/84) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं. 16/6/85–एम–3]

वेद प्रकाश गुप्त, निदेशक

S.O. 4130.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Professional Software Services Limited having its registered office at SPIC Centre, 97-Mount Road, Madras-600 032 under the said Act (Certificate of Registration No. 1714/84.

[No.16/6/85.M-III]

V. P. GUPTA, Director

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का.आ. 4131.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, तारीख 28 अगस्त, 1982 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2985 तारीख 6 अगस्त, 1982 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 21159.70 एकड़ (लगभग) या 8562.90 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अगस्त, 1984 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है।

अनुसूची

गोपाल प्रसाद ब्लाक

(तालचेर कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग संख्या राजस्व 1106/81

तारीख 28-12-81

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

क्रम सं.	ग्राम	तहसील	थाना	ग्राम सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मार्वाहिरिहरपुर	तालचेर	कोयला खान	55	धेनकानल	307.20	भाग
2.	चितलपुर	,,	,,	20	,,	416.00	भाग
3.	बानाबासपुर	,,	,,	41	,,	346.60	भाग
4.	पुराबेडा	,,	,,	40	,,	339.12	पूर्ण
5.	गोपाल प्रसाद खामर	,,	,,	19	,,	96.40	पूर्ण
6.	तेलीपुर	,,	,,	27	,,	368.83	पूर्ण
7.	आरक्षित वन	,,	,,	—	,,	430.00	पूर्ण
8.	गोपाल प्रसाद	,,	,,	18	,,	961.26	पूर्ण
9.	कुमुण्डा	,,	,,	11	,,	640.00	भाग

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	भालू गाडिया	तालचेर	कोयला खान	52	धेनकानल	670.77	पूर्ण
11.	बाधुबोले	,,	,,	44	,,	397.14	पूर्ण
12.	कुसुमपाल	,,	,,	12	,,	103.53	पूर्ण
13.	आसानाबाहली	,,	,,	1	,,	105.38	पूर्ण
14.	मालीबान्ध	,,	,,	54	,,	294.49	पूर्ण
15.	नौमुहित	,,	,,	36	,,	157.98	पूर्ण
16.	अन्तागाडिया	,,	,,	3	,,	155.93	पूर्ण
17.	कालमाचुईन	,,	,,	6	,,	1506.78	पूर्ण
18.	खुरिंगा	,,	,,	16	,,	162.04	पूर्ण
19.	सौलांडा	,,	,,	63	,,	1152,00	भाग
20.	बीराबारपुर	,,	,,	48	,,	77.29	पूर्ण
21.	माझीका	,,	,,	53	,,	158.66	पूर्ण
22.	सत्यबाडीपुर	,,	,,	62	,,	73.98	पूर्ण
23.	नाथागाम	,,	,,	34	,,	80.73	पूर्ण
24.	तेल ईपासी	,,	,,	26	,,	239.74	पूर्ण
25.	आसणबाहली	,,	,,	47	,,	393.76	पूर्ण
26.	छोटा बेरिनी	छेंदीपाडा	बरापाडा	64	,,	35.40	भाग
27.	कानकाराई	,,	,,	65	,,	588.80	भाग
28.	पिरखामान	हैंदीपाडा	जरापाडा	66	,,	246.16	पूर्ण
29.	बालीचन्द्रपुर	,,	,,	67	,,	438.74	पूर्ण
30.	आरक्षित वन (पी.एफ.)	,,	,,	—	,,	1514.00	पूर्ण
31.	नीसा	,,	,,	69	,,	152.00	भाग
32.	कालियाकाटा	,,	,,	70	,,	473.60	भाग
33.	रामाडीही	अंगुल	अंगुल	—	,,	230.40	भाग
34.	निरंजनपुर	,,	,,	8	,,	192.00	भाग
35.	निरंजनपुर (पी.आई.टी.) (II)	,,	,,	—	,,	527.20	भाग
36.	आरक्षित वन	,,	,,	—	,,	256.00	भाग
37.	भुवानपुर	,,	,,	10	,,	128.00	भाग
38.	जमुनाली	,,	,,	15	,,	50.20	भाग
39.	वडाझारन	,,	,,	5	,,	509.01	पूर्ण
40.	आरक्षित वन कुओ जंगल	,,	,,	—	,,	35.00	भाग
41.	बैठियानाली	,,	,,	4	,,	336.83	पूर्ण
42.	बारामहीटोला	,,	,,	7	,,	1132.17	भाग
43.	नाटाडा	,,	,,	3	,,	1429.21	पूर्ण
44.	अम्बापाल	,,	,,	1	,,	624.64	पूर्ण
45.	अम्बापाल जंगल	,,	,,	2	,,	388.40	पूर्ण
46.	सानमाहीटोला	,,	,,	6	,,	51.83	पूर्ण
47.	खाजूरिया	तालचेर	कोयलाखान	15	,,	202.51	पूर्ण
48.	नीलाद्रीपुर	,,	,,	35	,,	34.63	पूर्ण
49.	दामोल	,,	,,	25	,,	91.14	पूर्ण
50.	सारंग	,,	,,	60	,,	75.00	भाग
51.	नाकईपासी	,,	,,	32	,,	480.80	भाग
52.	प्रसान प्रसाद	,,	,,	39	,,	510.42	पूर्ण

कुल क्षेत्र : 21159.70 एकड़ (लगभग)
या : 8562.90 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा ग्राम कालियाकाटा से होकर जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख—ग रेखा ग्राम कालियाकाटा, रामाडीही, भुवानपुर, निरंजनपुर, आरक्षित वन, निरंजनपुर बी.आई.टी. II, वारामही टोला और जमुनाली से होकर ग्राम बाढ़ाआरन और आरक्षित वन कुओं जंगल की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती हुई आरक्षित वन कुओं जंगल से होकर जाती है बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग—घ रेखा तहसील अंगुल और तहसील तालचेर की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो नाटिडी ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ—ङ रेखा ग्राम कालमाखुईन और दानरा, ब्राह्मणबाहली और डानरा, प्रसान प्रसाद और दानरा, नाकईपासी और दानरा, दामोल और दानरा, पुन नाकइपासी और दानरा की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

ङ—च रेखा ग्राम नाकईपासी से होकर जाती है (जो अनंताबरिनी ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च—छ—ज रेखा ग्राम नाकईपासी और सारंग से होकर जाती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

ज—झ रेखा ग्राम खाजरिया और कान्थाबुआई की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती हुई ग्राम तोलोडो से होकर, ग्राम तेलीपुर और सोलोडो की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम बाना वासपुर से होकर जाती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

झ—ञ रेखा ग्राम बानाबासपुर, चितलपुर, मादाहरिहरपुर और कुनन्डा से होकर जाती है और बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।

ज—ट रेखा नदी से होकर, ग्राम डोटाबुरिनी और कानकाराई से होती हुई बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

ट—ठ रेखा सड़क की भागतः पूर्वी दिशा के साथ साथ जाती है और ग्राम नीसा में बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।

ठ—क रेखा, ग्राम सीसा से होकर, ग्राम नीसा और नाली ब्राह्मणी कालियाकाटा और आरक्षत वन की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ जाती है और आरक्षित बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा.सं. 19/28/82-सी.एल./सी.ए.]

टी.सी.ए. श्रीनिवासन, निदेशक

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O.4131.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2985 dated the 6th August, 1982 published in the Gazette of India, dated the 28th August, 1982, under Sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1959 (20 of 1957) the Central Government gave a notice of its intension to prospect for coal in lands meaturing 21159.70 acres (approximately) or 8562.90 hectares (approximately) in the loality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 28th August, 1984, as the period within which the Central Government may give notice of its intension to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Gopal Prasad Block

(Talcher Coalfield)

Drg. No. Rev./106/81 dated 28-12-81

(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Tahsil	Police Station	Village number	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mardahariharpur	Talcher	Colliery	55	Dhenkanal	307.20	Part
2.	Chitalpur	-do-	-do-	20	-do-	416.00	-do-
3.	Banabaspur	-do-	-do-	41	-do-	346.60	-do-
4.	Purabeda	-do-	-do-	40	-do-	139.12	Full
5.	Gopal Prasad Khamar	-do-	-do-	19	-do-	96.40	-do-
6.	Telipur	-do-	-do-	27	-do-	368.83	-do-
7.	Reserved forest	-do-	-do-	—	-do-	430.00	-do-
8.	Gopal Prasad	-do	-do-	18	-do-	961.26	-do-
9.	Kumunda	-do-	-do-	11	-do-	640.00	Part
10.	Bhalugadia	-do-	-do-	52	-do-	670.77	Full
11.	Baghubole	-do-	-do-	44	-do-	397.14	-do-
12.	Kusumpal	-do-	-do-	12	-do-	103.53	-do-
13.	Asanabahali	-do-	-do-	1	-do-	105.38	-do-
14.	Malibandha	-do-	-do-	54	-do-	294.49	-do-
15.	Nuamuhin	-do-	-do-	36	-do-	157.98	-do-
16.	Antagadia	-do-	-do-	3	-do-	155.93	-do-
17.	Kalamachuin	-do-	-do-	6	-do-	1506.78	-do-
18.	Khuringa	-do-	-do-	16	-do-	162.04	-do-
19.	Soloda	-do-	-do-	63	-do-	1152.00	Part
20.	Birabarpur	-do-	-do-	48	-do-	77.29	Full
21.	Majhika	-do-	-do-	53	-do-	158 66	-do-
22.	Satyabadipur	-do-	-do-	62	-do-	73 98	-do-
23.	Nathagan	-do-	-do-	34	-do-	80.73	-do-
24.	Teleipasi	-do-	-do-	26	-do-	239.74	-do-
25.	Brahmanbahali	-do-	-do-	47	-do-	393.76	-do-
26.	Chhotaberini	Chhendipada	Jarapada	64	-do-	35.40	Part
27.	Kankarai	-do-	-do-	65	-do-	588.80	-do-
28.	Pirakhaman	-do-	-do-	66	-do-	246.16	Full
29.	Balichandrapur	-do-	-do-	67	-do-	438.74	-do-
30.	Reserved Forest (P.F.)	-do-	-do-	—	-do-	1514.00	-do-
31.	Nisa	-do-	-do-	69	-do-	152.00	Part
32.	Kaliakata	-do-	-do-	70	-do-	473.60	Part
33.	Ramadihi	Angul	Angul	—	-do-	230.40	-do-
34.	Niranjanpur	-do-	-do-	8	-do-	192.00	-do-
35.	Niranjanpur BIT. II	-do-	-do-	—	-do-	527.20	-do-
36.	Reserved forest	-do-	-do-	—	-do-	256.00	-do-
37.	Bhubanpur	-do-	-do-	10	-do-	128.00	-do-
38.	Jamunali	-do-	-do-	15	-do-	50.20	-do-
39.	Badajharan	-do-	-do-	5	-do-	509.01	Full
40.	Reserved Forest Kueo Jungle	-do-	-do-	—	-do-	35.00	Part
41.	Bethianali	-do-	-do-	4	-do-	336.83	Full

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Baramahitole	Angul	Angul	7	Dhenkanal	1132.17	Part
43.	Natada	-do-	-do-	3	-do-	1429.21	Full
44.	Ambapal	-do-	-do-	1	-do-	624.64	-do-
45.	Ambapal Jungle	-do-	-do-	2	-do-	388.40	-do-
46.	Sanamahitola	-do-	-do-	6	-do-	51.83	-do-
47.	Khajuria	Talcher	Colliery	15	-do-	202.51	-do-
48.	Niladripur	-do-	-do-	35	-do-	34.63	-do-
49.	Damol	-do-	-do-	25	-do-	91.14	-do-
50.	Sarang	-do-	-do-	60	-do-	75.00	Part.
51.	Nakeipasi	-do-	-do-	32	-do-	460.80	-do-
52.	Prasan Prasad	-do-	-do-	39	-do-	510.42	Full

Total area :—21159.70 acres (approximately)

or

8562.90 hectares (approximately).

Boundary description :—

A—B Line passes through village Kaliakata and meets at point "B".

B—C Line passes through villages Kaliakata, Ramadihi, Bhubanapur, Niranjanpur, Reserve Forest, Niranjanpur BIT-II, Baramahitola, and Jamunali, passes along part common boundary of villages Badajharan and Reserve forest Kueo Jungle through reserved forest Keuo Jungle and meets at point 'C'.

C—D Line passes along the part common boundary of Tahsil Angul and Talhsil Tacher (which forms common boundary of Natidi Block and meets at point 'D'.

D—E Line passes along the part common boundary of villages Kalamachuin and Danra, Brahmanbahali and Danra, Prasan Prasad and Danra, Nakeipasi and Danra, Damol and Danra, again Nakeipasi and Danra and meets at point 'E'.

E—F Line passes through village Nakeipasi (which forms common boundary of Anantaberini Block) and meet at point 'F'.

F-G-H lines pass through villages Nakeipasi and Sarang and meet at point 'H'.

H—I Line passes along part common boundary of villages Khajuria and Kandhobuani, through village Soloda passes along common boundary of villages Telipur and Soloda, through village Banabaspur and meets at point 'I'.

I—J Line passes through villages Banabaspur, Chitalpur Mardahariharpur and Kununda and meets at point "J".

J—K Line passes through river through village Chhotaberini and Kankarai and meets at point 'K'

K—L Line passes along part eastern side of road and meets at point 'L', in village Nisa

L—A Line passes through village Nisa, passes along part common boundary of villages Nisa and Malibrahmani, Kaliahata and Reserve Forest and meets at starting point 'A'.

[No. 19/28/82-CL/CA]
T.C.A. SRINIVASAN, Director

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 4132:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4503 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जैगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधुना	बिधुना	चोंदा	56	0–12
				13	0–06
				20	0–05
				24	0–27
				48/2	0–02
				50	0–37
				18	0–29
				62/1	0–17
				15	0–26
				14	0–01
				8	0–11
				5	0–08
				51	0–13
				23	0–12
				16	0–06
				7	0–16
				6	0–44
				55	0–15
				52	0–12
				53	0–13
				54	0–39
				19	0–03
				49	0–02
				62/2	0–03

[सं. O–14016/393/84–जी पी]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4132.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4503 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Chordi	56	0–12
				13	0–06
				20	0–05
				24	0–27
				48/2	0–02
				50	0–37
				18	0–29
				62/1	0–17
				15	0–26
				14	0–01
				8	0–11
				5	0–08
				51	0–13
				23	0–12
				16	0–06
				7	0–16
				6	0–44
				55	0–15
				52	0–12
				53	0–13
				54	0–39
				19	0–03
				49	0–02
				62/2	0–03

[No. O-14016/393/84-GP]

का. आ. 4132.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. सं. 4504 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधुना	बिधुना	हरबंश पुर	451	1–36
				452	0–48
				448	0–02
				435	0–27
				434	0–57
				437	0–63
				431	1–20
				139/5	0–03
				440/1	0–01
				400	0–10
				401	0–15
				402	0–06
				403	0–22
				404	0–22
				405	0–15
				399	0–07
				406	0–08
				318	0–67
				81	0–18
				93	0–15
				94	0–10
				71	0–20
				72	0–16
				73	0–03
				70	0–60
				69	0–15
				68	0–12
				63	0–12
				64/1	0–02
				52	0–12
				53	0–03
				51	0–01
				50	0–67
				48	0–10
				43	0–08
				44	0–42
				42	0–02
				35	0–75
				22	0–37
				25	0–57
				24	0–20
				23	0–01
				36	0–03
				393	0–03
				394	0–01
				319	0–06
				92	0–10
				317	0–02

[सं. O–14016/34/804–जीपी]

S.O. 4133.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4504 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Harbans Pur	451	1–36
				452	0–48
				448	0–02

1	2	3	4	5	6
				435	0–27
				434	0–57
				437	0–63
				431	1–20
				439/5	0–03
				440/1	0–01
				400	0–10
				401	0–15
				402	0–06
				403	0–22
				404	0–22
				405	0–15
				399	0–07
				406	0–08
				318	0–67
				81	0–18
				93	0–15
				94	0–10
				71	0–20
				72	0–16
				73	0–03
				70	0–60
				69	0–15
				68	0–12
				63	0–12
				64/1	0–02
				52	0–12
				53	0–03
				51	0–01
				50	0–67
				48	0–10
				43	0–08
				44	0–42
				42	0–02
				35	0–75
				22	0–37
				25	0–57
				24	0–20
				23	0–01
				36	0–03
				393	0–03
				394	0–01
				319	0–06
				92	0–10
				317	0–02

[No. O-14016/394/84-GP]

का. आ. 4134.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय; पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4505 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	विधूना	विधूना	पूर्वावले	211	0–33
				210	0–17
				209	0–02
				208	0–38
				206	0–02
				205	0–47
				204	0–09
				203	0–48
				218	0–34
				219	0–33
				198	0–08
				197	0–11
				196	0–11
				220	0–04
				182	0–25
				221	0–77
				222	0–51

1	2	3	4	5	6
				166/412	0–42
				374	1–13
				375	0–79
				383/1	0–10
				383/2	0–16
				385	0–20
				384	0–83
				391	0–77
				393	0–42
				217	0–15

[सं. O- 14016/395/84-जी पी]

S.O. 4134.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4505 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot N.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna Purwa Valay		211	0–33
				210	0–17
				209	0–02
				208	0–38
				206	0–02
				205	0–47
				204	0–09
				203	0–48
				218	0–34
				219	0–33
				198	0–08
				197	0–11
				196	0–11
				220	0–04
				182	0–25
				221	0–77
				222	0–51
				166/412	0–42
				374	1–13
				375	0–79
				383/1	0–10
				383/2	0–16
				385	0–20
				384	0–83
				391	0–77
				373	0–42
				217	0–15

[No. O-14016/395/84-GP]

का०आ० 4135—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 4509 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	विधूना	विधूना	बहादुरपुर सहार	52	0–08
				54	0–02
				58	0–34
				57	0–35
				71	1–16
				75	0–12
				74	0–24
				88	0–15
				89	0–07
				90	1–25
				91	0–71
				92	0–04
				97	0–02
				98	0–02
				350	0–40
				351	0–23
				352	0–03
				353	0–14

[सं. O–14016/399/84-जी.पी.]

S.O. 4135.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4509 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Bahadur pur Shahar	52	0–08
				54	0–02
				58	0–34
				57	0–35
				71	1–16
				75	0–12
				74	0–24
				88	0–15
				89	0–07
				90	1–25
				91	0–71
				92	0–04
				97	0–02
				98	0–02
				350	0–40
				351	0–23
				352	0–03
				353	0–14

[No. O-14016/399/84-GP]

का. आ. 4136.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1501 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	उसरहा	615	0–31
				616	0–52
				621	0–06
				624	0–03
				626	0–95
				622	0–10
				623	0–30
				625	0–54
				715	0–03
				718	0–27
				719	0–17
				720	0–36
				722	0–68
				723	0–21
				724	0–22
				773	0–06
				782	0–01
				787	0–05
				786	0–05
				788	1–39
				801	0–87
				875	1–20
				876	1–07
				877	0–47
				878	0–02
				883	0–03
				885	0–03
				886	0–08
				892	0–27
				893	0–14
				894	0–06
				907	0–08
				911	0–03
				912	0–20
				913	0–24
				914	0–12
				915	0–01
				916	0–41
				923	0–03

[सं. O-14016/390/84-जी पी]

S.O. 4136.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4501 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Usraha	615	0–31
				616	0–52
				621	0–06
				624	0–03
				626	0–95
				622	0–10
				623	0–30
				625	0–54
				715	0–03
				718	0–27
				719	0–17
				720	0–36
				722	0–68
				723	0–21
				724	0–22
				773	0–06
				782	0–01
				787	0–05
				786	0–05
				788	1–39
				801	0–87
				875	1–20
				876	1–07
				877	0–47
				878	0–02
				883	0–03
				885	0–03
				886	0–08

1	2	3	4	5	6
				892	0-27
				893	0-14
				894	0-06
				907	0-08
				911	0-03
				912	0-20
				913	0-24
				914	0-12
				915	0-01
				916	0-41
				923	0-02

[No. O-14016/390/84/GP]

का. आ. 4137—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4506 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधुना	बिधुना	मोडक मीत	709	0-15
				720/1	0-18
				708	0-01
				710	0-09
				719	0-12
				718	0-32
				721	0-20
				722	0-64
				728	0-38
				727	0-03
				711	0-44
				729	0-48
				777	0-22
				778	0-18
				779	0-01
				776	0-61
				780	0-01
				781	0-18
				774/9	0-18
				774/7	0-18
				774/8	0-01
				756/1	0-92
				773	0-08
				767/5	0-08
				767/6	0-06
				768	0-10
				769	0-19
				764	0-12
				765	0-01
				766	0-10

[सं. O-14016/396/84-जी. पी.]

S.O. 4137.—Whecras by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4506 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Modak-meat	709	0-15
				720/1	0-18

1	2	3	4	5	6
				708	0–01
				710	0–09
				719	0–12
				718	0–32
				721	0–20
				722	0–64
				728	0–33
				727	0–03
				711	0–44
				729	0–48
				777	0–22
				778	0–18
				779	0–01
				776	0–61
				780	0–01
				781	0–18
				774/9	0–18
				774/7	0–18
				774/8	0–1
				756/1	0–92
				773	0–08
				767/5	0–08
				767/6	0–06
				768	0–10
				769	0–19
				764	0–12
				765	0–01
				766	0–10

[No. O—14016/396/84—GP]

का.आ. 4138.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4507 तारीख 12-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	विधूना	विधूना	मड़ियाई	524	0–49
				525	0–60
				531	0–06
				563	0–11
				568	0–38
				857	0–06
				858	0–78
				861	0–29
				862	0–79
				863	0–27
				564	0–78

[सं. O–14016/397/94–जी. पी.]

S.O. 4138.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4507 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Budhuna	Budhuna	Muryai	524	0–49
				525	0–60
				531	0–06
				563	0–11
				568	0–38
				857	0–06

1	2	3	4	5	6
				858	0 78
				861	0-29
				862	0-79
				863	0-27
				564	0-78

[No. O-14016/397/84—GP]

का.आ. 4139:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4509तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	भगवन्त पुर	171	0—57
				170	0—49
				179	0—73
				106	0—17
				111	0—03
				181	0—43
				92	0—55
				94	0—04
				95	0—07
				96	0—02
				98	0—09
				167	0—01
				107	0—27
				105	0—39
				104	0—27
				145	0—03

[सं. O—14016/392/84—जी० पी.]

S.O. 4139.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4509 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Bhagvantpur	171	0-57
				170	0-49
				179	0-73
				106	0-17
				111	0-03
				181	0-43
				92	0-55
				94	0-04
				95	0-07
				96	0-02
				98	0-09

1	2	3	4	5	6
				167	0-01
				107	0-27
				105	0-39
				104	0-27
				145	0-03

[No. O-14016/392/84—GP]

का. आ. 4140.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय, की अधिसूचना का. आ. सं. 554 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	धरमगद पुर	428	0-15
				432	0-01
				429	0-06
				430	0-03
				431	0-02
				433	0-48
				449	0-01
				435	0-01
				436	0-43
				437	0-16
				438	0-47
				440	0-36
				455	0-21
				459	0-12
				460	0-30
				461	0-17
				464	0-22
				521	0-02
				522	0-02
				519	0-16
				526	0-20
				527	0-01
				523	0-16
				529	0-16
				536	0-16
				535	0-13
				537	0-17
				905	0-06
				842	0-02
				841	0-04
				843	0-08
				844	0-22
				846	0-17
				849	0-15
				850	0-10
				848	0-04
				856	0-27
				857	0-35
				858	0-03
				859	0-02
				860	0-01
				862	0-16
				861	0-32
				872	0-65
				919	0-02
				997	0-06
				968	0-623
				969	0-10
				970	0-20
				976	0-05
				977	0-46
				1055	0-07

1	2	3	4	5	6
				1049	0-49
				1050	0-11
				1051	0-51
				1146	0-35
				1145	0-03
				1144	0-11
				1150	0-35
				1151	0-71
				1154	0-24
				1149	0-27
				1196	0-01
				1197	0-54
				1198	0-31
				1200	0-02
				1204	0-15
				1205	0-55
				1206	0-45
				1207	0-07
				1181	0-03
				1182	0-42
				1260/1	0-12
				1260/6	0-03
				520	0-30
				524	0-04
				531	0-02
				869	0-01
				1260/7	0-37

[सं. O-14016/01/85-जी. पी.]

S.O. 4140.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 554 dated 9-2-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acqured
1	2	3	4	5	6
Etawaha	Bidhuna	Bidhuna	Pharmagodpur	428	0-75
				432	0-01
				429	0-06
				430	0-03
				431	0-02
				433	0-48
				449	0-01
				435	0-01
				436	0-43
				437	0-16
				438	0-47
				440	0-36
				455	0-21
				459	0-12
				460	0-30
				461	0-17
				464	0-22
				521	0-02
				522	0-02
				519	0-16
				526	0-20
				527	0-01
				523	0-16
				529	0-16
				536	0-16
				535	0-13
				537	0-17
				905	0-06
				842	0-02
				841	0-04
				843	0-08
				844	0-22
				846	0-17
				849	0-15
				850	0-10
				848	0-04
				856	0-27
				857	0-35
				858	0-03
				859	0-02
				860	0-01
				862	0-46
				861	0-32
				872	0-65
				919	0-02
				997	0-36
				968	0-62
				969	0-10
				970	0-20
				976	0-05

1	2	3	4	5	6
				977	0-46
				1055	0-07
				1049	0-49
				1050	0-11
				1051	0-51
				1146	0-35
				1145	0-03
				1144	0-11
				1150	0-35
				1151	0-71
				1154	0-24
				1149	0-27
				1106	0-01
				1197	0-54
				1198	0-31
				1200	0-02
				1204	0-15
				1205	0-55
				1206	0-45
				1207	0-07
				1181	0-03
				1182	0-42
				1260/1	0-12
				1260/6	0-03
				520	0-30
				524	0-04
				531	0-02
				869	0-01
				1260/7	0-37

[No. O-14016/01/85—GP]

का० आ० 4141.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं. 855 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	लखनो	871	0-68
				870	0-22
				869	0-58
				868	0-30
				867	0-26
				862	0-40
				861	0-34
				858	0-34
				857	0-08
				1060	0-20
				1061	0-71
				1062	0-01
				1063	0-02
				1047	0-52
				1046	0-06
				1138	0-22
				1139	0-24
				1141	0-01
				1142	0-10
				1143	0-36
				1145	0-10
				1146	0-05
				1147	0-10
				1153	0-22
				1154	0-32
				1175	0-75
				1194	0-33
				1195	0-45
				1196	0-08
				1199	0-32
				1200	0-35
				1203	0-05
				1204	0-82
				1205	0-01

1	2	3	4	5	6
				1206	0-80
				1288	0-24
				1290	0-30
				1291	1-04
				1298	0-01
				1300	1-40
				1302	0-42
				1304	0-10
				1305	0-60
				1307	0-03
				1308	0-42
				1319	0-02
				1326	0-76
				1603	0-74
				1542	0-40
				1543	0-08
				1544	0-42
				1545	0-10
				1562	0-20
				1563	0-40
				1573	0-10
				1576	0-10
				1583	0-22
				1584	0-02
				1585	0-56
				1586	0-33 1638
				1638	0-20
				1054	0-05
				1050	0-30
				1051	0-70
				1052	0-05
				1053	0-10
				1156	0-26
				1549	0-25
				1587	0-10

[सं. O-14016/02/85—जी.पी.]

S.O. 4141.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 555 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barcilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Luckno	871	0-68
				870	0-22
				869	0-58
				868	0-30
				867	0-26
				862	0-40
				861	0-34
				858	0-34
				857	0-08
				1060	0-20
				1061	0-71
				1062	0-01
				1063	0-02
				1047	0-52
				1046	0-06
				1138	0-22
				1139	0-24
				1141	0-01
				1142	0-10
				1143	0-36
				1145	0-10
				1146	0-05
				1147	0-10
				1153	0-22
				1154	0-32
				1155	0-75
				1194	0-33
				1195	0-45
				1196	0-08
				1199	0-32
				1200	0-35
				1203	0-05
				1204	0-82
				1205	0-01
				1206	0-80
				1288	0-24
				1290	0-30
				1291	1-04
				1298	1-01
				1300	1-40

1	2	3	4	5	6	
				1302	0 42	
				1304	0-01	
				1305	0-60	
				1307	0-03	
				1308	0-42	
				1319	0 02	
				1326	0-76	
				1603	0-74	
				1542	0-40	
				1543	0-08	
				1544	0-42	
				1545	0-10	
				1562	0-20	
				1563	0-40	
				1573	0-10	
				1576	0-10	
				1583	0 22	
				1584	0-02	
				1585	0 56	
				1586	0-33	1638
				1638	0-20	
				1054	0-05	
				1050	0-30	
				1051	0-70	
				1052	0-05	
				1053	0-10	
				1156	0-26	
				1549	0-25	
				1587	0 10	

[No. O-14016/02/85-G.P.]

का. आ. 4142.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 556, तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	विधूना	विधूना	कैथाबा	11	0-30
				12	0-08
				13	0-29
				14	0-05
				15	0-64
				179	0-30
				178	0-30
				177	0-24
				175	0-37
				174	0-30
				173	0-56
				187	0-03
				188	0-10
				172	0-57
				159	0-05
				158	0-60
				157	0-37
				170	0-30
				166	0-25
				165	0-27
				164	0-13
				167	0-01
				168	0-20
				162	0-21
				172	0-31
				173	0-02
				298	0-31
				281	0-18
				282	0-06
				283	0-02
				287	0-43
				272	0-22
				273/1	0-44
				293	0-19
				1114	0-14
				1112	0-51
				1113	0-34
				1126	0-04
				1128	0-22

1	2	3	4	5	6
				1129	0–25
				1130	0–16
				1136	0–27
				1135	0–09
				1061	0–02
				1051	0–23
				1062	0–07
				1063	0–18
				1056	0–36
				1057	0–12
				1050	0–02
				1049	0–15
				1001	0–68
				1002	0–05
				1017	0–16
				1018	0–03
				1015	0–08
				1016	0–06
				1013	0–02
				1014	0–86
				985	0–01
				984	0–02
				987	0–21
				986	0–03
				970	0–15
				10	0–05
				1277	0–15
				1305	0–25
				1307	0–06
				1308	0–03
				1306/1444	0–06
				1306	0–35
				1321	0–41
				1322	0–12
				1323	0–08
				1314	0–09
				1320	0–78
				1330	0–35
				1331	0–15
				1334	0–88

[सं. O–14016/03/85–जी.पी.]

S.O. 4142.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 556 dated 9th February, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area Aquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Kaithawa	11	0 30
				12	0-08
				13	0-29
				14	0 05
				15	0-64
				179	0–30
				178	0-30
				177	0-24
				175	0-37
				174	0–30
				173	0-56
				187	0-03
				188	0–10
				172	0–57
				159	0–05
				158	0–60
				157	0–37
				170	0–30
				166	0-25
				165	0-27
				164	0-13
				167	0-01
				168	0–20
				162	0–21
				172	0–31
				173	0-02
				298	0–31
				281	0 18
				282	0-06
				283	0-02
				287	0–43
				272	0–22
				273/1	0-44

1	2	3	4	5	6
				293	0-19
				1114	0-14
				1112	0 51
				1113	0-34
				1126	0-04
				1128	0-22
				1129	0 25
				1130	0-16
				1136	0-27
				1135	0-09
				1061	0 02
				1051	0-23
				1062	0-07
				1063	0 18
				1056	0-36
				1057	0-12
				1050	0-02
				1049	0-15
				1001	0-68
				1002	0 05
				1017	0-16
				1018	0-03
				1015	0-08
				1016	0-06
				1013	0-02
				1014	0-86
				984	0-01
				985	0-02
				987	0-21
				986	0-03
				970	0-15
				10	0-05
				1277	0-15
				1305	0-25
				1307	0-06
				1308	0 03
				1306/1444	0 06
				1306	0-35
				1321	0-41
				1322	0-12
				1323	0-08
				1314	0-09
				1320	0-78
				1330	0-35
				1331	0-15
				1334	0-88

[No. O-14016/03/85-G.P.]

का. आ. 4143.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 557 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	रायपुर कैथाना	69	0—12
				34	0—15
				38	0—01
				37	0—11
				27	0—02
				41	0—01
				42	0—28
				43	0—02
				44	0—15
				45	0—11
				46	0—08
				47	0—10
				51	0—30
				52	0—30
				53	0—42
				54	0—02
				49	0—11
				50	0—01

[सं० ओ-14016/04/85-जी पी]

S.O. 4143.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 557 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Raipur Kaithwa	69	0-12
				34	0-15
				38	0-01
				37	0-11
				27	0-02
				41	0-01
				42	0-28
				43	0-02
				44	0-15
				45	0-11
				46	0-08
				47	0-10
				51	0-30
				52	0-30
				53	0-42
				54	0-01
				49	0-11
				50	0-01

[No. O-14016/04/85-G.P.]

का. आ. 4144:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 558 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	गुलरिहा	100	1-22
				101	0-04
				102	0-83
				104	0-11
				111m	1-58
				112	0-16
				113	0-05
				115	0-11
				116	0-41
				123m	0-08
				146	0-29
				149	0-25
				150	0-61
				152m	0-63
				156m	0-20
				176	0-02
				177	0-12
				180	0-14
				181	0-03
				182	0-20
				183	0-57
				184	0-35
				187	0-02
				188	0-02
				193	0-28
				202	0-89

1	2	3	4	5	6
				203	0–70
				204	0–01
				230	0–06
				235	0–01
				237	0–02
				238	0–67
				199	0–02

[सं० ओ-14016/05/85-जी पी]

S.O. 4144.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 558 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira -Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Gularia	100	1–22
				101	0–04
				102	0–83
				104	0–11
				111m.	1–58
				112	0–16
				113	0–05
				115	0–11
				116	0–41
				123m.	0–08
				146	0–29
				149	0–25
				150	0–61
				152m.	0–63
				156m.	0–20
				176	0–02
				177	0–12
				180	0–14
				181	0–03
				182	0–20
				183	0–57
				184	0–35
				187	0–02
				188	0–02
				193	0–28
				202	0–89
				203	0–70
				204	0–01
				230	0–06
				235	0–01
				237	0–02
				238	0–67
				199	0–02

[No. O-14016/05/85-GP]

का० आ० 4145.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के संत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 559 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	बांधमऊ	52	0–77

[सं० ओ-14016/06/85-जी पी]

S.O. 4145.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 559 dated 9-2-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuma	Bidhuma Mau	Bandh	52	0-77

[No. O-14016/06/85-GP]

का. आ. 4146.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 560 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनें बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	असेनी	958	0–01
				957	0–29
				656	0–50
				951	0–16
				947	0–11
				946	0–03
				945	0–04
				944	0–04
				943	0–08
				942	0–08
				940	0–02
				939	0–01
				934	0–12
				930	0–45
				929	0–02
				928	0–23
				927	0–01
				926	0–42
				925	0–05
				924	0–02
				923	0–42
				909	0–07
				897	0–33
				896	0–01
				895	0–02
				894	0–42
				893	0–32
				862	0–02
				848	0–60
				846	0–32
				843	0–02
				841	0–02

[सं० आ०-14016/07/85-जी पी]

S.O. 4146.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 560 dated 9th February, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawa	Bidhuna	Bidhuna	Asai	958	0-01
				957	0-29
				656	0-50
				951	0-16
				947	0-11
				946	0-03
				945	0-04
				944	0-04
				943	0-08
				942	0-08
				940	0-02
				939	0-01
				934	0-12
				930	0-45
				929	0-02
				928	0-23
				927	0-01
				926	0-42
				925	0-05
				924	0-02
				923	0-42
				909	0-07
				897	0-33
				896	0-01
				895	0-02
				894	0-42
				893	0-32
				862	0-02
				848	0-60
				846	0-32
				843	0-02
				841	0-02

[No. O-14016/07/85-GP]

का. आ. 4149:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 583 तारीख 23-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए, अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
फर्रुखाबाद	छिबरामऊ	ताल ग्राम	ताल ग्राम	1666/1	1-25
				1666/6	0-82
				1671/1	0-04
				1672	0-36
				1673	0-11
				1674	0-19
				1675	0-10
				1681	1-30
				1682	0-03
				1683	0-25
				1684	0-72
				1995	0-38
				1997	0-12
				1998	0-49

1	2	3	4	5	6
				2002	0-03
				2008	0-32
				2021	0-01
				2022	0-07
				2023	0-23
				2024	0-27
				2033	0-22
				2034	0-13
				2027	0-02
				2035	0-17
				2036	0-06
				2037	0-04
				2038	0-03
				2039	0-02
				2043	0-37
				2044	0-01
				2045	0-01
				2046	0-28
				2093	0-03
				2096	0-06
				2097	0-09
				2098	0-22
				2099	0-67
				2100	0-03
				2107	0-14
				2425	0-12
				2106	0-03
				2449	0-71
				2450	0-96
				2451	0-06
				2447	0-11
				2636	0-02
				2638	0-18
				2639	0-22
				2650	0-80
				2674	0-07
				2676/2	0-25
				2676/1	0-12
				2677	0-19
				2678	0-36
				2679	0-03
				2680	0-01
				2681	0-01
				2683	0-69
				2681	0-24
				2685	0-57
				2686	0-01
				2687	0-01
				2692	0-03
				2895	0-06
				2906	0-03
				2908	0-32
				2909	0-10
				2911	0-12
				2913	0-31
				2914	0-15
				2915	0-28
				2918	0-53
				2907	0-46
				3043	0-60
				3044	0-02
				3045	0-10
				3046	0-13
				3729	0-65
				3731	0-63
				3732	0-08
				3759	3-42
				3763	0-20
				3766	0-39
				3767	0-45
				3768	0-12
				3769	0-06
				3789	0-05
				3806	1-24
				3807	0-93
				3811	0-39
				3812	0-45
				3813	0-24
				3815	0-53
				3816	0-01
				3817	0-80
				3818	0-15
				3819	0-45
				3093	0-50
				3730	0-33

[सं० अ(-14016/32/85-जी पी]

S.O. 4147.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 583 dated 23rd January, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right

of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Farukhabad	Chhibra Mau	Talgram	Talgram	1666/1	1–25
				1666/6	0–82
				1671/1	0–04
				1672	0–36
				1673	0–11
				1674	0–19
				1675	0–10
				1681	1–30
				1682	0–03
				1683	0–25
				1684	0–72
				1995	0–38
				1997	0–12
				1998	0–49
				2002	0–03
				2008	0–32
				2021	0–01
				2022	0–07
				2023	0–23
				2024	0–27
				2033	0–22
				2034	0–13
				2027	0–02
				2035	0–17
				2036	0–06
				2037	0–04
				2038	0–03
				2039	0–02
				2043	0–37
				2044	0–01
				2045	0–01
				2046	0–28
				2093	0–03
				2096	0–06
				2097	0–09
				2098	0–22
				2099	0–67
				2100	0–03
				2107	0–14
				2425	0–12
				2106	0–03
				2449	0–71
				2450	0–96
				2451	0–06
				2447	0–11
				2636	0–02
				2638	0–18
				2639	0–22
				2650	0–80
				2674	0–07
				2676/2	0–25
				2676/1	0–12
				2677	0–19
				2678	0–36
				2679	0–03
				2680	0–01
				2681	0–01
				2683	0–69
				2681	0–24
				2685	0–57
				2686	0–01
				2687	0–01
				2692	0–03
				2895	0–06
				2906	0–03
				2908	0–32
				2909	0–10
				2911	0–12
				2913	0–31
				2914	0–15
				2915	0–28
				2918	0–53
				2907	0–46
				3043	0–60
				3044	0–02
				3045	1–10
				3046	0–13
				3729	0–65
				3731	0–63
				3732	0–08
				3759	3–42
				3763	0–20
				3766	0–39
				3767	0–45
				3768	0–12

1	2	3	4	5	6
			Tal-	3769	0-06
			gram	3780	0-05
			(Contd.)	3806	1-24
				3807	0-93
				3811	1-39
				3812	0-45
				3813	0-24
				3815	0-53
				3816	0-01
				3817	0-80
				3818	0-15
				3819	0-45
				3093	1-50
				3730	0-33

[No. O-14016/32/85-GP]

नई दिल्ली 29 अगस्त 1985

का. आ. 4148.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2582 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित रकबा ब० वि० वि०
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	नगल-हुसैन	2	0-07-00
				3	0-01-00
				5	0-00-12
				7	0-10-05
				8	0-05-08
				9	0-19-05
				10	0-10-04
				13	0-10-04

[सं० O-14016/363/85-जी पी]

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4148.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2582 dated 30-5-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the *Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act*, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
					B. V. V.
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Nagla Hussain	2	0-07-00
				3	0-01-00
				5	0-00-12
				7	0-10-05
				8	0-05-08
				9	0-19-04
				10	0-10-04
				13	0-10-05

[No. O-14016/363/85-GP]

का. आ. 4149.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1791 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाध्याओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेल—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित रकबा हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियार	नदुवापुर नरोया	28	0630
				29	0630
				30	0250
				31	0400
				32	0150
				896/189	0250
				75	0450
				77	1000
				78	0075
				81	1300
				82	1800
				85	0850
				86	1250
				132	0480
				133	0720
				134	2700
				135	0400
				138	0500
				139	0500
				140	0900
				142	0600
				143	0420
				153	1900
				179	0380
				180	0130
				182	0630
				183	0780
				184	1900
				186	0630
				187	0840
				195	1250
				196	0380
				197	1800
			नदुवापुर नरोया (जारी)	201	1340
				363	0100
				375	1500
				405	0450
				407	0380
				414	0800
				415	0500
				416	0600
				418	0650
				420	0105
				421	0780
				422	0750
				423	0720
				424	0100
				425	0780
				433	0600
				434	1860
				435	0300
				439	2730
				440	1370
				445	0590
				446	0700
				447	4810
				448	0050
				188	0050
				154	0025

[सं० O-14016/237/85-जी पी]

S.O. 4149.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1791 dated 16-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired Hactre
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katyari	Naduapul	28	0630
			Narotha	29	0630
				30	0250
				31	0400
				32	0150
				896/189	0250
				75	0450
				77	1000
				78	0075
				81	1300
				82	1800
				83	0850
				86	1250
				132	0480
				133	0720
				134	2700
				135	0400
				138	0500
				139	0500
				140	0900
				142	0600
				143	0420
				153	1900
				179	0380
				180	0130
				182	0630
				183	0780
				184	1900
				186	0630
				187	0840
				195	1250
				196	0380
				197	1800
				201	1340
				363	0100
				375	1500
				405	0450
				407	0380
				414	0800
				415	0500
				416	0600
				418	0650
				420	0105
				421	0780
				422	0750
				423	0720
				424	0100
				425	0780
				433	0600
				434	1860
				435	0300
				439	2730
				440	1370
				445	0590
				446	0700
				447	4810
				448	0050
				188	0050
				154	0025

[No. O-14016/237/85-GP]

का. आ. 4150.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1792 तारीख 16-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित रकबा		
					ब	बि	बि
1	2	3	4	5	6		
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	अम्हरौल	31	—	5	—5
				27	1	5	5
				38	1	6	5
				39	—	6	—
				501	—	6	10
				39	—	14	7
				95	—	2	—
				91	1	7	—
				93	2	2	—
				80	—	8	2
				81	—	14	5
				170	—	9	12
				171	—	—	5
				172/1	—	1	10
				172/2	—	4	10
				173	—	5	10
				177/1	—	4	—
				177/2	—	15	10
				228	—	7	—

1	2	3	4	5	6
			अम्हरौल	229	— 18 10
				226	— 1 10
				227/1	1 — 10
				225	— 3 10
				227/2	— 5 —
				346	— 2 10
				347	— 6 —
				350	— — 15
				544	— 11 10
				549	— 15 —
				390	— 2 5
				551	— 4 —
				552	1 — —
				555	— 10 15
				545	1 1 —
				538	1 7 5
				522	— 2 5
				521	— 12 10
				539	— 13 —
				520	— 1 16
				500	1 1 10
				499	— 6 5
				556/1	— — 3
				348	— 4 7
				556/2	— — 5

[सं. O-14016/238/85-जं प]

S.O. 4150.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1792 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired B	V	V
1	2	3	4	5		6	
Hardoi	Bilgram	Kotyani	Bramh-rauli	31	—	5	5
				37	1	5	5
				38	1	6	5
				39	—	6	—
				501	—	6	10
				39	—	14	7
				95	—	2	—
				91	1	7	—
				93	2	2	—
				80	—	8	2
				81	—	14	5
				170	—	9	12
				171	—	—	5
				171/1	—	4	10
				172/2	—	4	10
				173	—	5	10
				177/1	—	4	—
				177/2	—	15	10
				228	—	7	—
				229	—	18	10
				226	—	1	10
				227/1	1	—	10
				225	—	3	10
				227/2		5	—
				346	—	2	10
				347	—	6	—
				350	—	—	15
				544	—	11	10
				549	—	15	—
				390	—	2	5
				551	—	4	—
				552	1	—	—
				555	—	10	15
				545	1	1	—
				538	1	7	5
				522	—	2	5
				521	—	12	10
				539	—	13	—
				520	—	1	16
				500	1	1	10
				499	—	6	6
				556/1	—	—	3
				348	—	4	7
				556/2	—	—	5

[No. O-14016/238/85-GP]

का. आ. 4151.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1795 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा – बरेली– जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पाली	चकोती कला	207/2	3–8–0
				209/4/2	0–4–6
				209/6	0–15–0
				209/7	1–4–0
				209/8	0–4–4
				210/10	0–15–0
				210/11	3–15–0
				211/6	1–7–10
				211/7	3–9–0
				214/2	3–1–0
				214/3,4	1–10–0
				215	0–5–0

[सं. O– 14016/241/85– जी पी]

S.O. 4151.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1795 dt. 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government, directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe line project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area B.V.V.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Sahabad	Pali	Chakoti-Kalan	207/2	3–8–0
				209/4/2	0–4–6
				209/6	0–15–0
				290/7	1–4–0
				209/8	0–4–4
				210/10	0–15–0
				210/11	3–15–0
				211/6	1–7–10
				211/7	3–9–0
				214/2	3–4–0
				214/3, 4	1–10–0
				215	0–5–0

[No. O-14016/241/85-GP]

का.आ. 4155.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 1756 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	बि. वि. वि.
हरदोई	शाहाबाद	पाली	बेहरी	39	0–7–14
				40	0–7–10

2	3	4	5	6
			41	0-2-2
			42	0-2-10
			44	0-4-5
			45	0-6-0
			47	0-3-15
			51	0-2-10
			52	0-4-0
			53	0-7-18
			54	0-3-12
			479	0-12-0
			480	0-5-0
			489	0-16-4
			490	0-0-10
			491	0-10-0
			493	0-1-4
			494	1-0-8
			495	0-0-10
			496	0-12-10
			40/636	0-7-0

[सं. O-14016/242/85-जी पी]

S.O. 4152.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1756 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
					B. V. N.
Hardoi	Shahabad	Pali	Behti	39	0-7-14
				40	0-7-10
				41	0-2-2
				42	0-2-10
				44	0-4-5
				45	0-6-0
				47	0-3-15

1	2	3	4	5	6
				51	0-2-10
				52	0-4-0
				53	0-7-18
				54	0-3-12
				479	0-12-0
				480	0-5-0
				489	0-16-4
				490	0-0-10
				491	0-10-0
				493	0-1-4
				494	1-0-8
				495	0-0-10
				496	0-1 -10
				40/636	0-7-0

[No. O-14016/24 /85-GP]

का. आ. 4153.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1758 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों का उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा— बरेली— जगदीशपुर गैस-पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. बि. बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	करियारी	बहेटाराम पुरा	17	0-4-0
				18	1-7-12

[सं. O-14016/244/85-जीपी]

S.O. 4153.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1758 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B. V. Y.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Dehtaram Pura	17	0-4-0
				18	1-7-12

[No. O 14616/244/85-GP]

का. आ. 4154.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1759 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा– बरेली– जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा हक्टर
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	चाऊपुर	16	-0670
				17	-0250
				21	-3000
				23	-0200
				24	-0450
				25	-1300
				26	-1000
				1024/26	-0150
				54	-0630
				55	-3600
				56	-0550
				57	-1400
				65	-0650
				66	-1650
				106	-1350
				107	-1125
				108	-0900
				109	-1350
				150	-0525
				727	-1650
				464	-0200
				665	-0100
				725	-1300
				724	-1024
				722	-1050
				717	-0700
				719	-0300
				720	-3000
				680	-0100
				681	-0250
				682	-0100
				683	-0600
				684	-0100
				689	-1010
				690	-0750
				692	-0350
				694	-1100
				695	-2400
				696	-0700

1	2	3	4	5	6
			चाऊंपुर	699	—2500
				700	—0200
				701	—0050
				871	—0200 —0750
				876	—1150
				877	—1300
				879	—0050
				880	—2600
				881	—0500
				870	—5000
				871	—0550
				885	—1100
				886	—1200
				887	—0900
				890	—1200
				910	—1700
				911	—2300
				913	—0075
				907	0050
				918	0150
				919	0075
				921	0750
				923	2150
				930	1450
				931	1700
				932	1250
				697	0125
				929	0030

[सं. ओ—14016/245/85—जी पी]

S.O. 4154.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1759 dated 16-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ. Gas Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area required in Hector
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgarm	Katyari	Chanpur	16	—0670
				17	—0250
				21	—3000
				23	—0200
				24	—0450
				25	—1300
				26	—1000
				1024/26	—0150
				54	—0630
				55	—3600
				56	—0550
				57	—1400
				65	—0650
				66	—1650
				106	—1350
				107	—1125
				108	—0900
				109	—1350
				150	—0525
				727	—1650
				664	—0200
				665	—0100
				725	—1300
				724	—1050
				722	—1050
				717	—0700
				719	—0300
				720	—3000
				680	—0100
				681	—0250
				682	—0100
				683	—0600
				684	—0100
				689	—1010
				690	—0750
				692	—0350
				694	—1100
				695	—2400
				696	—0700
				699	—2500
				700	—0200
				701	—0050
				874	—0200
				875	—0750
				876	—1150
				877	—1300
				879	—0050
				880	—2600
				881	—0500
				870	—0050
				871	—0550
				885	—1100
				886	—1200
				887	—0900
				890	—1200
				910	—1700
				911	—2300
				913	—0075

1	2	3	4	5	6
			Chanpur	907	– 0050
				918	– 0150
				919	—0075
				921	– 0750
				928	—2150
				930	—1450
				931	– 1700
				932	– 1250
				697	—0125
				929	– 0030

[No. O –14016/245/85-GP]

का. आ. 4155.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1763 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा– बरेली– जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. बि. बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पाली	अलियापुर	238	0–7–4

[सं. ओ– 14016/249/ 85– जी पी]

S.O. 4155.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1763 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (i) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargans	Village	Plot No.	Area in B B B
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Alyapur	238	0—7 - 4

[No. O –14016/249/85-GP]

का. आ. 4156.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1764 तारीख 16-4-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा ब. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहा-बाद	पाली	उबरिया कला	1	0–6–0
				80/1	0–13–0
				81/2	1–9–0
				83/1	0–0–10
				82	3–10–0
				4	0–0–5
				85/1	0–12–0
				122/2	2–10–10
				123/4	0–3–0
				125/2	2–14–0
				126/2	1–15–0
				127/2	0–12–10
				134/2	1–5–0
				135/2	0–13–5

[सं. O–14016/250/85-जीपी]

S.O. 4156.—Wheeras by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1764 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barcilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Ubraia Kalan	1	0-6-0
				80 1	0-13-0
				81/2	1-9-0
				83/1	0-0-10
				82	3-10 0
				84	0–0–5
				85/1	0-12-0
				122/2	2-10-10
				123/4	0 3 0
				125/2	2-14-0
				126/2	1-15-0
				126/2	0-12-10
				134/2	1-5-0
				135/2	0-13-5

[No. O—14016/250/85-GP]

का. आ. 4157.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1765 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा ब. वि. विसे
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहा-बाद	पाली	कन्हारी	283/1	0–12–10
				284/2	1–15–0
				285/1	4–16–10

[सं. O–14016/251/85-जीपी]

S.O. 4157.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1765 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government, vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Kanhaki	283/1	0-12-10
				284/2	1-15-0
				285/1	4-16-10

[No. O -14016/251/85-G P]

का. आ. 4158.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 1766 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. बि. बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पाली	कनकापुर उबरिया	525	0-0-10
				526	0-3-10
				532	0-14-10
				533	0-6-10
				536	0-2-10
				558/1	0-5-7
				558/2	0-10-13
				559/2	1-1-10
				561/2	0-9-0
				560	1-8-0

[सं. O-14016/252/85-जीपी]

S.O. 4158.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1766 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Kanakapur Libaria	525	0-0-10
				526	0-3-10
				532	0-14-10
				533	0-6-10
				536	0-2-10
				558/1	0-5-7
				558/2	0-10-13
				559/2	1-1-10
				561/2	0-0-0
				560	1-8-0

[No. O-14016/252/85-GP]

का०आ० 4159.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं० 1754 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है, कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित रकबा हेक्टर
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	ढिकवन	6	.0500
				7	.2000
				8 के	.0100
				8	.0300
				14के एच	.0400
				15	.1000
				16	.0600
				17	.0700
				27के	4000
				28	.0600
				29	.0750
				30	.0400
				31	.2600
				32	.0050
				193	.0750
				213	.0400
				214	.2000
				498	.0750
				500	0750
				501	.0750
				502	.0250

[सं. ओ-14016/271/85-ज.प]

S.O. 4159.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1754 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the scheduled appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Hectares
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Dhak-Pura	6	.0500
				7	.2000
				8K	.0100
				8	.0300
				14kh	.0400
				15	.1000
				16	.0600
				17	.0700
				27k	.4000
				28	.0600
				29	0.750
				30	0.400
				31	.2600
				32	.0050
				193	.0750
				213	.0400
				214	.2000
				498	.0750
				500	.0750
				501	.0750
				502	.0250

[No. O-14016/271/85-GP]

का.आ. 4160.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1728 तारीख 16-4-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अक्त उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा वे. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिल-ग्राम	कटियारी	सुरजपुर दर्जन पजीशाला	270ख	0–18–0
				280ख	2–0–10
				279क	0–16–0
				281	0–1–0
				282	0–7–16
				283	0–2–0
				284	0–0–5
				315	0–2–10
				316	0–10–0
				318	0–16–0
				319	0–10–0
				322मि	0–6–0
				233/1	0–5–10
				232	1–4–0
				233/2	2–0–5
				231/1	1–8–0
				231/2	1–6–10
				359क	0–10–0
				368	1–3–0
				369क	0–12–0
				369ख	0–17–10
				371	1–8–0
				373	1–8–0
				374क	1–16–0

[सं. O-14016/273/85-जीपी]

S.O. 4160.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1728 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user to the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Surajpur Durjan Panjshala	270kb	0–18–0	
				280kb	2–0–10	
				279k	0–16–0	
				281	0–1–0	
				282	0–7–16	
				283	0–2–0	
				284	0–0–5	
				315	0–2–10	
				316	0–10–0	
				318	0–16–0	
				319	0–10–0	
				322Mi	0–6–0	
				233/1	0–5–10	
				232	1–4–0	
				233/2	2–0–5	
				231/1	1–8–0	
				231/2	1–6–10	

1	2	3	4	5	6
				359k	0-10- 0
				368	1- 3- 0
				369k	0-12- 0
				369kh	0-17-10
				371	1- 8- 0
				373	1- 8 -0
				374k	1-16- 0

[No. O-14016/273/85-GP]

का०आ० 4161.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1729 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा व. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिल-ग्राम	कटि-यारी	भूपति-पुर नगरा	19	0-9-0
				20	0-17-2
				30	0-6-6
				31	0-5-15
				32	1-6-0
				331/1	0-4-7
				33/2	0-4-8
				49	0-9-9
				54	0-14-4
				50	0-3-10
				53	0-3-0
				55	0-10-4
				56	1-2-0
				58	0-3-0
				59	0-6-10
				60	0-4-4
				66	0-8-10
				65	0-17-6
				68	0-2-0
				95	0-15-16
				94	0-03-0
				100	0-2-0
				101	0-6-0
				102	0-1-10
				106	0-15-0
				107	0-4-10
				108	0-4-13
				109	0-6-6
				158	0-12-0
				106	0-15-0
				107	0-4-10
				108	0-4-13
				109	0-6-6
				158	0-12-0
				160	0-3-0
				159	0-15-0
				161	0-3-0
				162	0-3-10
				46	0-0-1
				157	0-1-10
				67	0-0-10

[सं. O-14016/274/85-जी.पी.]

S.O. 4161.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1729 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Bhopatipur Nagra	19	0- 9- 0
				20	0-17- 2
				30	0- 6- 6
				31	0- 5-15
				32	1- 6- 0
				331/1	0- 4- 7
				33/2	0-40- 8
				49	0- 9- 9
				54	0-14- 4
				50	0- 3-10
				53	0- 3- 0
				55	0-10- 4
				56	1- 2- 0
				58	0- 3- 0
				59	0 -6-10
				60	0- 4- 4
				66	0- 8-10
				65	0- 17-6
				68	0 -2- 0
				95	0-51-16
				94	0-03- 0
				100	0 -2- 0
				101	0- 6- 0
				102	0- 1-10
				106	0-15- 0
				107	0 4- 10
				108	0- 4-13
				109	0- 6- 6
				158	0-12- 0
				106	0-15- 0
				107	0 -4-10
				108	0- 4-13
				109	0- 6- 6
				158	0-12- 0
				160	0- 3- 0
				159	0-15- 0
				161	0- 3- 0
				162	0- 3-10
				46	0- 0- 1
				157	0-1-10
				67	0- 0-10

[No. O-14016/274/85-GP]

का.आ. 4162.—अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1730 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. बि. बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	सरेखर	256	0-0-10
				303	0-1-0
				304	0-8-0
				305	0-9-0
				308	0-17-5
				312	0-10-0
				313	0-16-0
				317	0-16-0
				318	0-13-0
				452	0-7-0
				457	0-9-0
				458	0-11-0
				469	0-8-10
				470	0-5-10
				507	0-6-0
				510	0-2-0
				511	0-9-0
				512	0-10-0
				517	0-1-0.
				518	0-6-0
				498	0-11-0
				499	0-11-10
				500	0-0-10
				307	0-3-0
				314	0-1-10
				453	0-2-0
				319	0-0-10
				468	0-1-5
				491	0-2-0

[सं. O-14016/275/85-जी.पी.]

S.O. 4162.—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1730 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgam	Katiyari	Saresar	256	0-1-10
				303	0-1- 0
				304	0-8- 0
				305	0-9- 0
				308	0-17- 5
				312	0-10- 0
				313	0-16- 0
				317	0-16- 0
				318	0-13- 0
				452	0- 7- 0
				457	0- 9- 0
				458	0-11- 0
				469	0- 8-10
				470	0- 5-10
				507	0- 6- 0
				510	0- 2- 0
				511	0- 9- 0
				512	0-10- 0
				517	0- 1- 0
				518	0- 6- 0
				498	0- 11-0
				499	0 11-10
				500	0- 0-10
				307	0- 3- 0
				314	0- 1-10
				453	0- 2- 0
				319	0- 0-10
				468	0- 1- 5
				491	0- 2- 0

[No. O-14016/275/85-GP]

का०आ० 4163.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के (पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 1774 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : देवालखेड़ा, तहसील: ईसागढ, जिला: गुना, राज्य: मध्य प्रदेश

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	174	0.178
2.	175	0.240
3.	178/2	0.052
4.	178/1	0.042
5.	179	0.199
6.	189	0.219
7.	190	0.178
8.	191/1	0.105
9.	191/2	0.052
10.	193	0.270
11.	176	0.027
12.	177	
13.	178/3	
14.	192/3	0.093
15.	194	0.020
16.	197	0.051
17.	198	0.105
18.	199	0.125
19.	200	0.005
20.	201	
21.	210	0.260
22.	212	0.314
23.	188/1	0.005
24.	215	0.251
25.	217	
26.	216	0.658
27.	218	
28.	228	

1	2	3
29.	219	—
30.	220	—
31.	229	—
32.	230	—
33.	233	0.314
34.	235/2	0.081
35.	236/5	0.005
36.	234	0.083
37.	364	0.073
38.	376/1	0.188
39.	378/1	0.031
40.	376/3	0.083
41.	381/2	0.010
42.	382/2	
43.	381/1	0.410
44.	382/1	
45.	384/2	0.230
46.	384/1	0.178
47.	385	0.345
48.	388	0.449
49.	389	0.010
50.	379/3अ	0.052
51.	376/5	0.366
52.	376/4	0.126
योग :—कुल क्षेत्रफल		6.483

[सं. O-14016/292/85-जी पी]

S.O. 4163.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1747 dated 27th April, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ,

And whereas the Competent Authority has under Sub Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this decalaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipeline Project

Village : DYPALKHEDI; Tehsil : Isagarh; Disst : Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U in Hector
1.	174	0.178
2.	175	0.240
3.	178/2	0.052
4.	178 1	0.042
5.	179	0.199
6.	189	0.219
7.	190	0.178
8.	191/1	0.105
9.	191/2	0.052
10.	193	0.270
11.	176	0.027
12.	177	
13.	178/3	
14.	192/3	0.093
15.	194	0.020
16.	197	0.051
17.	198	0.105
18.	199	0.125
19.	200	0.005
20.	201	
21.	210	0.260
22.	212	0.314
23.	188/1	0.005
24.	215	0 251
25.	217	
26.	216	0.658
27.	218	
28.	228	
29.	219	
31.	220	
32.	230	
33.	233	0.314
34.	235/2	0.081
35.	236/5	0.005
36.	234	0.083
37.	364	0.073
38.	376/1	0.188
39.	378/1	0.031
40.	376/3	0.083
41.	381/2	0.010
42.	382/2	
43.	381/1	0.410
44.	382/1	
45.	384/2	0.230
46.	384/1	0.178
47.	385	0 345
48.	388	0.449
49.	389	0.010
50.	379/3 KH	0.052
51.	376/5	0.366
52.	376/4	0.126
	TOTAL AREA	6.483

[No. O-14016/292-85-GP]

का.आ. 4164.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 2329 तारीख 18-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी. वि. बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	करियारा	कफपुरा	20	0–14–10
				19	0–17–0
				29	0–2–0
				30	0–19–0
				31	0–4–0
				32	0–14–0
				73	0–14–0
				74	0–7–0
				75	0–8–0
				76	0–7–0
				116	0–2–10
				117	0–18–0
				122	0–14–10
				167	0–6–0
				132	0–18–0
				173	0–12–10
				174	0–2–0
				175	0–11–0
				183	0–5–0
				184	0–12–0
				185	0–1–0
				244	0–5–0
				245	0–4–10
				246	0–3–0
				247	0–2–10
				246	0–3–10
				251	0–3–0
				253	0–3–0
				255	0–2–10
				256	0–5–0
				257	0–9–0
				258	0–13–0
				281	0–2–10
				318	0–2–10
				319	0–6–0
				320	0–4–0
				321	0–2–10
				322	0–6–0
				323	0–3–10
				324	0–3–0
				325	0–5–0
				328	0–1–0
				329	0–17–0
				253	0–0–10
				330	0–19–10
				331	0–12–10
				348	0–8–0
				349	0–0–10
				350	0–7–0
				352	0–0–10
				467	0–6–0
				468	0–7–0
				492	0–5–0
				493	0–9–0
				499	0–3–10
				500	0–5–0
				501	0–0–10
				601	0–4–0
				602	0–9–0
				498	0–4–0
				604	0–5–0
				642	0–6–0
				644	0–8–10
				645	0–11–10
				646	0–7–0
				648	0–1–0
				647	0–13–0
				707	0–18–0
				708	0–13–0
				709	0–3–0
				710	0–11–0
				711	0–1–0
				712	0–7–0
				814	0–13–0
				118	0–2–0

1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कांटियारी	ढकपुरा	121	0-1-0
				133	0-1-0
				326	0-0-5
				327	0-0-5
				603	0-2-0
				491	0-2-0
				497	0-1-0
				469	0-2-0
				488	0-0-10

[सं. O-14016/345/85-जी. पी.]

S.O. 4164.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2329 dated 18th May, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahasil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Dhakpura	20	0-14-10
				19	0-17-0
				29	0-2-0
				30	0-19-0
				31	0-4-0
				32	0-14-0
				73	0-14-0
				74	0-7-0
				75	0-8-0
				76	0-7-0
				116	0-2-10
				117	0-18-0
				122	0-14-10
				167	0-6-0
				132	0-18-0
				173	0-12-10
				174	0-2-0
				175	0-11-0
				183	0-5-0
				184	0-12-0
				185	0-1-0
				244	0-5-0
				245	0-4-10
				246	0-3-0
				247	0-2-10
				248	0-3-10
				251	0-3-0
				252	0-3-0
				255	0-2-10
				256	0-5-0
				257	0-9-0
				258	0-13-0
				281	0-2-10
				318	0-2-10
				319	0-6-0
				320	0-4-0
				321	0-2-10
				322	0-6-0
				323	0-3-10
				324	0-3-0
				325	0-5-0
				328	0-1-0
				329	0-17-0
				253	0-0-10
				330	0-19-10
				331	0-12-10
				348	0-8-0
				349	0-0-10
				350	0-7-0
				352	0-0-10
				467	0-6-0
				468	0-7-0
				492	0-5-0
				493	0-9-0
				499	0-3-10
				500	0-5-0
				501	0-0-10
				601	0-4-0
				602	0-9-0
				498	0-4-0
				604	0-5-0
				642	0-6-0
				644	0-8-10
				645	0-11-10
				646	0-7-0
				648	0-1-0
				647	0-13-0
				707	0-18-0
				708	0-13-0
				709	0-3-0
				710	0-11-0
				711	0-1-0
				712	0-7-0
				814	0-13-0
				118	0-2-0
				121	0-1-0
				133	0-1-0
				326	0-0-5
				327	0-0-5
				603	0-2-0
				491	0-2-0
				497	0-1-0
				469	0-2-0
				488	0-0-10

[No. O-14016/345/85-GP]

का. आ. 4165—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ 226 020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा बि.बि.बि		
1	2	3	4	5	6		
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	लालपुर छिबला				
				71	6	15	10
				82	2	02	
				81	—	—	10
				105	—	01	
				199	—	03	
				201	—	03	05
				106	0	15	10
				200	2	15	—
				198	—	01	
				197	—	01	
				166	—	02	
				109	—	04	10
				193	—	02	10
				110	—	06	10
				194	—	05	10
				114	—	01	10
				115	—	01	
				116	—	—	10
				195	—	06	10
				117	—	—	10
				118	—	09	
				120	—	10	10
				121	—	07	
				123	—	04	
				124	—	08	
				167	1	—	
				125	—	—	02
				166	—	02	15
				165	—	—	10
				134	—	01	08
				164	—	17	
				163	—	03	18
				158	—	—	10
				159	—	—	05
				135	1	02	—
				136	—	04	05
				137	—	—	05
				144	—	02	
				145	—	—	—
				146	—	09	
				143	1	06	10
				150	—	02	08
				482	—	02	10
				171	—	—	05
				157	—	—	08
				122	—	—	10
				46	24	3	14

[सं. O-14016/488/85-जी. पी.]

S.O. 4165.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareily-Jagdishpur Pipeline Project

District	Tahasil	Pargana	Village	Plat No.	Area in acquired B.B.B.
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Lalpur Chibn	71	6 –15 - 10
				82	– 2—02
				81	— — 10
				105	— 01
				199	— 03
				201	— 03 05
				106	-- 15 10
				200	2 15 —
				198	— 01
				197	— 01
				196	— 02

1	2	3	4	5	6
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Lalpur China	109	-04-10
				193	-02-10
				110	-06-10
				194	-05-10
				114	-01-10
				115	-01-
				116	- -10
				195	-06-10
				117	- -10
				118	-09-
				120	-10-10
				121	-07-
				123	-04-
				124	-08-
				167	-1 -
				125	- -02
				166	-02-15
				165	- -10
				134	-01-08
				164	-17-
				163	-03-18
				158	- -10
				159	- -05
				135	1-02-
				136	-04-05
				137	- -05
				144	-02-
				145	2- -
				146	-09-
				143	1-06-10
				150	-02-08
				482	-02-10
				171	- -05
				157	- -08
				122	- -10
				46	24-3-14

[No. O-14016/488/85-GP]

का. आ. 4166—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1760 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा वि. वि. वि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहबाद	पाली	धौरालिया		
				15	0-10-0
				29	0-17-15
				31	0-5-0
				32	0-3-4
				33	0-14-0
				34	0-4-5
				35	0-0-5
				36	1-4-12
				39	1-4-12
				42	1-5-16
				55	1-6-8
				56	0-8-0
				62	1-11-5
				63	0-10-0
				67	1-4-12
				68	0-2-0
				65	0-7-10

[सं. O-14016/248/85-जी. पी.]

एम. एम. श्रीनिवासन, उपसचिव

S.O. 4166.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1760 dated 16th April, 1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tahasil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired in B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pali	Dhauralia	15	0-10-0
				29	0-17-15
				31	0-5-0
				32	0-3-4
				33	0-14-0
				34	0-4-5
				35	0-0-5
				36	1-4-12
				39	1-4-12
				42	1-5-16
				55	1-6-8
				56	0-8-0
				62	1-11-5
				63	0-10-0
				67	1-4-12
				68	0-2-0
				65	0-7-10

[No. O-14016/246/85-GP]

M. S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

का०आ० 4167—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम 1898 (1898 का 9) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आस्ट्रेलिया में फैले हुए पक्षी इन्फलुजा को देखते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए आस्ट्रेलिया से शुद्ध नस्ल तथा पीढी पूर्व (ग्रेंड पैरेन्ट) स्टाक, सेने वाले अण्डों आदि सहित कुक्कुट का भारत में आयात करने पर रोक लगाती है ।

[सं० 50-4/84-एल०डी०टी० (ए० क्यू)]

डी० डी० नाहर, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(Deptt. of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4167.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby prohibits import into India of poultry including pureline and grand-parent stock, hatching eggs, etc. from Australia for a period of 6 months from the date of issue of this notification in view of outbreak of avian influenza in that country.

[No. 50-4/84-LDT(AQ)]

D. D. NAHAR, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

का०आ० 4168—अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रोजेक्ट एवं इक्विपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान ग्रुप महा प्रबंधक श्री जी० एस० गुप्ता को उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, अनुसूची "ग" के रु० 3500-4000 के वेतनमान में, एतद्द्वारा पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं प्रशासन) नियुक्त करते हैं ।

[सं० ए०वी० 24020/6/84-ए०ए० (एफ-II)]

एस० सी० कोहली, वित्त नियंत्रक

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th August, 1985

S.O. 4168.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Gupta presently Group General Manager, Projects & Equipment Corporation of India Limited as a whole-time Member (Finance & Administration) in the International Airports Authority of India, in the Schedule 'C' scale of Rs. 3500—4000, for a period of three years from the date of his assuming charge of the post.

[No. AV-24020/6/84-AA(F.II)]

S. C. KOHLI, Financial Controller.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

का० आ० 4169—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने नडन्तुनगर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-85 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-9/85-पी एण्ड बी (पीटी)]

के० पी० शर्मा, सहायक महा निदेशक (पी०एण्ड०बी)

MINISTRY OF COMMUNICATION

(P&T Board)

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4169.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Posts and Telegraphs, hereby specified 1-9-1985 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Naduvathunagar Telephone Exchange Kerala Circle.

[No. 5-9/85-PHB(PT)]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1985

का.आ. 4170—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि० सिर्सा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8 अगस्त 1985 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th August, 1985

S.O. 4170.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employer in relation to the Hindustan Commercial Bank Limited, Sirsa and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th August, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 61 of 1984; Chandgarn

PARTIES :

Employers in relation to the management of Hindustan Commercial Bank Ltd.

AND

Their Workman : Sh. Suresh Kumar

APPEARANCESS :

For the Employers—Shri A. C. Jain.

For the workman—Petitioner with Sh. L. S. Sachdeva.

ACTIVITY : Banking. STATE : Punjab.

AWARD

Dated the 1st of August, 1985

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide their order No. L-12012/9/84/D.IVA dated the 2nd of February, 1985 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication—

"Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Ltd; H.O. Kanpur in relation to their Branch Office Sirsa (Haryana) in terminating the services of Sh. Sursh Kumar, Peon-cum-Waterman with effect from 20-1-83 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitld ?"

2. During the course of hearing a suggestion was floated to the management to reconsider their stand because the petitioner was reported to be a poor man with family liabilities and on their own showing there was no charge of mis-conduct against him. In all fairness to them, the Management responded with grace and offerd to provide fresh employment to the petitioner in the regular cadre of their subordinate staff. They also agreed to give him certain qualified notional benefits provided it did not bind them with monetary liability in any shape whatsoever. The proposition was accepted by the petitaloner.

3. As such on taking down the statements of the parties on my record and hearing them, I return my Award in the following terms which are quite fair to the petitioner/workman:—

(A) The Respdt. Management would take immediate steps to provide employment to the petitioner in the regular cadre of its subordinate staff; in case the matter is delayed for any administrative or such other reasons, the petitioner would report for duty at their Sirsa Branch on 16-8-1985 and thence forth shall deemed to be on duty for all intents and purposes.

(B) Even though the petitioner would not be entitled for any monetary benefits including backwages, bonus or such service facilities which could be encashed yet he shall deemed to be in continuous service from the stage of his initial appointment for the purpose of seniority and notional increments etc.

Chandigarh

1-8-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer.

[No. L-12012/9/84-D.IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

का. आ. 4171—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 अगस्त, 1985 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4171.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2 Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on the 13th August, '85.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/34 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Nagpur.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—(1) Shri A. G. Ramani, Assistant Law Officer

(2) Shri A. E. Kulkarni, Officer M.M.G. Sc. II, Regional Officer, Nagpur

For the Workmen—Shri S D. Phadke, President, SBI & S. B. Employees' Union, Nagpur.

STATE : Maharashtra INDUSTRY : Banking

Bombay, dated the 5th August, 1985

AWARD

By their order No. L-12012(201)/84-D.II(A) dated 12-3-85 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.—

"Whether the action of the management of State Bank of India Region III, Nagpur in terminating the services of Shri B. D. Uike, Bank Guard, Chandur Railway Branch with effect from 25-6-1983 is justified. If not, to what relief the workman is entitled?"

2. After holding an enquiry into the alleged misconduct of the workman concerned, on the strength of the finding noted by the Enquiry Officer by order dated 16-6-1983 the workman, a Watchman, serving at the relevant time in the Branch of the State Bank of India at Chandur was discharged from service and although an appeal was preferred against the said order the appellate authority namely the Chief Regional Manager rejected the same on 5-9-1983. Since a dispute was raised before the Assistant Labour Commissioner (C) ultimately the same led to the reference.

3. By award part I dated 7-5-1985 on hearing the parties and going through the enquiry papers the Tribunal held the enquiry to be not legal and invalid and at the same time at the request of the management gave them an opportunity to adduce evidence to prove the misconduct before the Tribunal. However as per para. 12 of the Award Part I this opportunity was restricted to the misconduct which was held proved by the Enquiry Officer and not that which was held not proved. It is not clear why there are two enquiry reports first dated 18-3-82 and the second dated 26-2-1983 but since there was a second enquiry, the first one is deemed to have been obliterated and findings as to which of the charges were held established reference necessarily will have to be made to the second enquiry. From the findings as noted in the report it is seen that regarding the chargesheet dated 2-12-1981 relating to the incident alleged to have occurred on 22-11-1981 the Enquiry Officer noted the finding that it is proved that Shri Uike has committed offence of indecent behaviour on the Bank premises and disobedience by not allowing the Branch Manager in Bank premises by uttering unparliamentary language. The charge against the workman that he remained absent unauthorisedly from duty on 8-11-1981 and 20-11-1981 was held not establishment. From the chargesheet dated 4-1-1982 relating to the alleged incident of 3-12-1981 the finding was that charge No. 1 namely on 3-12-1981 at about 6.30 P.M. the workman reported for duty from 6.30 to 2.30 a.m. undr influence of liquor and accompanied by lady proved. Regarding charge No. 2 namely that on the very date at about 7.00 p.m. while under influence of liquor, the workman abused the Branch Manager and threatened him by using the words "you will be beaten in the bazar with shoes at the hands of a female", It was held proved that the workman misbehaved with the Branch Manager on that day but the charge of being under the influence of liquor was held not proved. These details are stated because only the charges held proved by the enquiry officer are the subject matter of consideration before the Tribunal.

4. Relying upon the opportunity given to the management they have examined two witnesses SlShri Jayant Vishnu Pant Pandey and Ramesh Vishnupant Madhikar, respectively then Branch Manager and Agricultural Development Manager attached to the said branch during the relevant time. The evidence of Shri Pandey is that on 22-11-1981 at about 6.30 or 7 P.M. when he returned to Chandur Railway town and was taking tea at the house of Shri Madhikar, the Badli Watchman Shri Paighan arrived the said house complaining of assault by the workman i.e. Uike the watchman or Bank guard. Shri Paighan had injuries and was bleeding and his clothes were soiled with blood, therefore in order to see as to what was the matter the witness along with Shri Madhikar. Shri Kapre and Shri Paighan proceeded to the Branch when they saw Shri Uike present. The witness says that on seeing them the workman closed the door of the Branch whereupon they knocked on the door and asked Shri Uike to open it in reply to which he i.e. workman asked them to go away and further threatened that he would shoot them. According to the witness the watchman is permitted to have a Gun because his name is shown as retainer in the Gun Licence of the Bank and he was also permitted to carry live cartridges. Shri Paigan therefore was sent to the Police Station for lodging complaint and although an attempt was made to contact the Regional Manager the said attempt failed as they could not get connections.

5. The Branch Manager then says that on 3-12-1981 at about 6.30 or 7.00 P.M. the Messenger in the service of the Bank arrived at his residence and told that Shri Uike accompanied by a lady had visited the Branch and he (Uike) entrusted to the Messenger an application after having exchange of words. It was reported that no Watchman was present on duty in the Branch. The Branch Manager therefore immediately rushed to the Bank and at that time he was accompanied by S/Shri Padnavi and others who were also serving in the same branch. The Badli Watchman Paighan when called for arrived and at about the same time the workman accompanied by a female arrived on the scene and he i.e. the workman told that he had submitted an application for leave and asked the Branch Manager whether he was not sanctioning the same. It is further stated that the workman expressed that the Branch Manager cannot do anything ill to him i.e. Shri Uike but against that he i.e. Watchman would beat the witness with shoes at the hands of a female. Those persons who were present persuaded the workman to leave the place and accordingly he left the place with his female companion. The Police protection was therefore sought and was given.

6. Shri Ramesh Vishnupant Madhikar also speaks of these incidents and says that on 22-11-1981 on arrival at the Branch in the company of the Branch Manager when the workman was asked to open the door which he had closed on seeing the Branch Manager and others, he threatened that he would shoot them. He further says that 15 or 20 days thereafter his son informed him of commotion in front of the Branch and to see what was the matter he went there when he found the Branch Manager present and when asked, the witness was informed by him that Shri Uike had threatened saying that he should sanction leave and that Branch Manager cannot do anything ill to him against which the Watchman can beat him in the Bazar at the hands of a female.

7. I have gone through the evidence of these witnesses who are responsible Bank Officers and I am convinced that what they stated must be true. An attempt was made to suggest that they are biased against the workman but I do not find any force in the same. The record shows, the matter was reported to the Police and they had taken action although no charge-sheet could be lodged because steps were not taken by the Police in the prescribed time. Yet there is absolutely no reason to disbelieve these witness when they say that on the first day the workman threatened to shoot them which he could very easily have done because he kept a fire arm and on subsequent day he had threatened to beat the Branch Manager in the Bazar. It is pertinent to note that although there was this evidence on record before the Tribunal, the workman who is denying the charge never stepped into the witness box. I have carefully gone through the evidence as it stands and I am convinced that even under the S.B.I. Group instructions the Branch Manager was entitled to visit the Branch outside office hours and he has justified in trying to go there in order to see what was the matter. The attempt therefore to suggest that even the Branch Manager could not have entered the Branch and if the Watchman had threatened to shoot there was nothing illegal, must fail. Under the S.B.I. group instructions paragraph 56(vii) and (ix) nobody can order the bank premises outside office hours without the agent's permission meaning thereby that agent himself can visit the branch, which is also evident from sub-para (ix) which casts a duty on the agent or other supervisory officials to inspect the Guard at irregular intervals to see that proper watch is being maintained. The Branch Manager therefore when an untowards incident was reported had every right to visit the Branch and varify the facts and the workman by threatening to shoot him or to beat him must be held to be guilty of gross-misconduct as per para 521(4)(b) and (e) of the Sastri Award.

8. Once we arrive at this conclusion the next question is whether the order of discharge is harsh and disproportionate. It is already noticed that the workman was armed with a fire arm under a licence in the name of the Bank, he being a retainer and when he was threatening to shoot, it is really good luck of the Branch Manager that the intention was not coverted into action. Such threatening whether to shoot or beat in the Bazar that too on the premises of the Bank where the Agent or the Branch Manager had every right to go, can never be countenanced and if the Bank has decided to discharge such a Watchman from service, I do not think that such action of the Bank was harsh and the punishment disproportionate. I therefore hold that the order of discharge passed against the workman terminating his service was fully justified and calls for no interference.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.
[No. L-12012/201/84-D.II(A)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ. 4172—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-8-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4172.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act ,1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/33 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Nagpur

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—1. Shri A. K. Ramani, Assistant Law Officer 2. Shri A. E. Kulkarni, Officer M.M.G. Sc. II, Regional Office, Nagpur.

For the Workmen—Shri S. D. Phadke, President, SBI and S. B. Employees' Union, Nagpur.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 1st August, 1985

AWARD

By their Order No. L-12012/200/84-D.II (A) dated 12-3-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of State Bank of India Region III, Nagpur in terminating the services of Shri B. M. Godhane from 24-6-83 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The order of discharge passed against the workman Shri B. M. Godhane, a Driver in the service of the State Bank of India was a result of chargesheet indicating the workman firstly that on 7-8-1981 while returning from Chandur Bazar on official duty the workman had driven the Bank's vehicle at a high speed prejudicial to the interest of the jeep and its occupants due to his consuming alcohol and knocked down two persons and also caused damage to Bank's jeep and secondly that he i.e. the workman had also unauthorisedly allowed an outsider to occupy the Bank's jeep while returning from Chandur Bazar. An enquiry was held on these charges and ultimately the Enquiry Officer on going through the evidence adduced before him held that the workman was negligent in his duty and caused damage to jeep No. M.H.R. 4757 and that while driving the vehicle the workman was under influence of alcohol. So far as the second charge was concerned he held that the same is not proved. Similarly part of the first charge of knocking down two persons while driving the vehicle. The Enquiry Officer's finding dated 1-12-1982 culminated in the order of discharge passed by the Regional Manager-cum-Disciplinary Authority dated 15-6-1983, being aggrieved of which the workman had preferred an appeal to the Chief Regional Manager but by his order dated 30-9-1983 the appellate Authority refused to interfere in the order and rejected the appeal. Ultimately this led to the present reference.

3. The parties had filed respectively the statement of claim and written statement whereby on one hand the workman challenges the validity of the enquiry agaist which the management re-affirmed the same but on hearing the parties by Award Part I dated 1-5-1985 the enquiry was held vitiated and therefore cannot be said to be valid, yet as there was a request of the Bank to allow them to prove the misconduct before the Tribunal an opportunity was given and the matter was heard.

4. During the course of subsequent hearing there is evidence of Shri A. R. Oka, Cashier in the service of M/s. Gadre Motors, Amravati, MW-1, Shri S. D. Deogongkar, the then Branch Manager of Amravati Branch in whose disposal the jeep was placed at the relevant time, MW-2 and lastly the evidence of Shri L .B. Gadre, Senior partner in Gadre Motors at Amravati. The workman chose not to adduce any evidence either of himself or of any witness.

5. Since an opportunity has been given to the bank to establish the misconduct the question which arose for determination at this stage and my findings thereon are :—

Issues	Findings
1. Whether the misconducts as alleged are proved ?	No
2. If yes whether the punishment as awarded is harsh and disproportionate ?	Does not arise
3. Is the action of the management in discharging the workman justified ?	Not justified
4. What award ?	As per award.

REASONS

6. We have already seen that the charge against the workman is that he had driven the vehicle while under the influence of alcohol, was negligent in his duty and caused damage to the jeep. So far as the remaining part of charge No. 1 and the entire charge No. 2 were concerned the enquiry officer himself held them to be not proved, therefore there was no question of their proving before the Tribunal nor there is any evidence led during the enquiry here. The question naturally would be whether there is material to hold that at the relevant time the Driver i.e. the workman concerned was under influence of alcohol and further was negligent in his duties as a result of which the Bank had suffered great loss.

7. That the vehicle met with an accident and that for carrying out the repairs to the vehicle the Bank had spent Rs. 10,511.85 has been proved by the evidence of Shri Gadre proprietor of Gadre Motors, Amravati and his employee Shri Oka who prepared the bills and works as Cashier. Although there was an attempt made to suggest that the bill was an inflated bill and that the vehicle might not have been damaged to this extent as tried to be projected the evidence of these two witnesses especially the proprietor of Garage disproves the said suggestion. I conclude relying on this evidence and further relying on the evidence of the Branch Manager that on the relevant date i.e. 7-8-1981 the vehicle had met with an accident while it was being driven by the workman who was in the service of the Bank as a Driver and that for carrying out the repairs the Bank had to incur an expense of Rs. 10,000 and odd.

8. This however cannot conclude the matter and unless there is sufficient evidence to establish the alleged part played by the workman, conclusion of proof of misconduct would not be justified. We have already seen the charges levelled against the workman which are stated to be gross-misconduct. Under the Sastri Award Para 521(4)(c) drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour on the premises of the bank is one of the gross-misconduct so also under sub-clause (j) gross negligence or negligence involving or likely to involve the bank in serious loss is another gross misconduct for which the workmen can be discharged or dismissed.

9. Firstly it was urged that the Driver was guilty of drunkenness and while he was under influence of alcohol he drove the vehicle and caused the accident. Now if we go to the list of gross-misconduct as contemplated by para 521 (4)(c) of the Sastri Award it is evident that drunkenness or disorderly behaviour has to be on the premises of the Bank while in the instant case the accident admittedly occured not on the bank premises but far away from the said place on the public road. In M/s. Glaxo Laboratories (I) Ltd. case reported in (1984) 1 Supreme Court cases 1 while considering the relevant clause in the Standing Orders of the company where drunkenness committed within the premises of the establishment or in the vicinity thereof it was held that to be a misconduct. The misconduct must have connection with the place of work and the employer has no extraterritorial jurisdiction. No doubt it is true that being in-charge of the vehicle as Driver it was the duty of the workman to drive the jeep and it is necessarily in public places or on highways but this cannot mean that he was for the said purpose on the premises of the Bank. Therefore assuming that there is evidence of drunkenness, when sub-clause (4)(c) requires drunkenness on the premises of the bank, before a workman is held guilty for that misconduct, that charge cannot be said to have been substantiated.

10. But still the question would be whether drunkenness has been established. Since the enquiry is held vitiated and therefore opportunity was given to the bank to establish or substantiate the charge, whatever ingredient of the charge is to be established the bank has to establish it by cogent evidence in support thereof. Since drunkenness or being under influence of alcohol would require the word of medical expert who would speak authoritatively on the said point, the word of Medical Officer who is alleged to have examined the Driver immediately on his arrest was essential which the Bank failed to adduce. In the absence thereof the bank is relying upon the evidence of the Branch Manager, Ex. MW-2 who in examination in chief stated that on 7-8-1981 when the Driver returned to the Branch with the vehicle he found him to be under influence of alcohol and he had bruises on his body. The Branch Manager even if held to be expert in the bank affairs cannot be an expert in medical science unless he proves to be so and therefore his word that he found the workman under influence of alcohol would be nothing but a word of layman having no evidential value. No conclusion therefore is possible on the strength of his statement that the Driver was drunk or that he was under influence of alcohol. He even found the workman smelling of Alcohol but this would not lead to any conclusion one way or other in the absence of direct evidence.

11. In the written arguments the Bank is also relying upon para 521(4)(d) of the Sastri Award which says that wilful damage or attempt to cause damage to the property of the Bank would amount to gross misconduct. It is important to note that the chargesheet does not speak of any wilful damage nor there is evidence to show that the workman deliberately caused damage to the vehicle the property of the bank. Reliance therefore on para 521(4)(d) of the Sastri Award at this stage in the first place would not be permissible and particularly in the absence of any evidence. The question then is whether the workman was guilty of gross misconduct of negligence involving or likely to involve the bank in serious loss in other words is he guilty of misconduct as defined in clause (j) sub-clause (c) of para 521 of the Sastri Award. For the said purpose the bank is placing reliance of proof of damage whereby the bank had incurred expense of Rs. 10,511.85 for carrying out the repairs to the vehicle and also on the maxim res ipsa loquitur. So far as the damage to the vehicle is concerned there is absolutely no reason to disbelieve the statements of three witnesses of management including Shri Gadre and the bills submitted and the payments received by him. This shows that on the relevant date i.e. on 7-8-1981 while the vehicle was moving from Chandur to Amravati it met with a serious accident and that at the relevant time the workman was driving the vehicle. The Magistrate who heard the criminal case against the workman even went to the length of holding absence of proof of vehicle being driven by the workman but the fact that he was driving the vehicle at the relevant time is not denied before the Tribunal. However, merely because the vehicle suffered severe damage would not automatically lead to any inference of negligence or rash and negligent driving. There is no evidence barring the proof of damage suggesting any rash or negligent driving on the part of the Driver and in my view when there is no such proof the management cannot invoke maxim res ipsa loquitur. Had there been some proof in this regard like the evidence of eye witnesses, the failure of the workman to step in the witness box might have been a circumstance appearing against him but when there is absolutely no evidence attributing negligence to him, failure of the workman to appear before the Tribunal cannot be a proof of his act. The record shows that the vehicle met with the accident on the highway where the speed as admitted by Shri Gadre of 50—60 Km. per hour cannot be said to be excessive but would be normal speed. If the vehicle was being driven assuming at this speed met with an accident the damage as seen is likely to result but in the absence of any other material on record it would not lead to any conclusion of rashness or negligent driving. Shri Gadre has admitted that the vehicle is kept on low gear while climbing a gradient and if the vehicle dashes against any object major damage is likely to be resulted. In the appeal Memo as well as during the enquiry the plea of the workman was because it was raining the road had become slippery and while trying to avoid a bullock which had suddenly run on the road the vehicle turned turtle. There is nothing to disprove this statement and if the workman is to be dismissed or discharged on the ground of gross negligence the burden cannot be thrown on the workman but some evidence would be necessary on behalf of the management rebuttal for which the workman would be responsible. However as already stated there is absolutely no evidence except the proof of damage but by itself it would not lead to proof of ingredients as incorporated in the chargesheet.

12. The result is that drunkenness or being under influence of alcohol is not established nor it is established that the workman was grossly negligent nor that as a result of this gross negligence the Bank suffered heavy loss. The net result therefore would be that no ingredient of the charge is proved and so the order of discharge can never be said to be justified. The Bank is therefore directed to reinstate the workman forthwith. Treating the period from the date of suspension till the date of award as that of period of suspension the Bank shall make payment.

Award accordingly.

M. A. DPSHPANDE, Presiding Officer

[No. L-12012/200/84-D.II (A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1985

का०आ० 4173.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनमे कर्मचारियों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, पुणे ।
2. सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, नागपुर ।
3. सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, चन्द्रपुर ।
4. सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, वास्को ।
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) का कार्यालय, भुसावल ।
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) का कार्यालय, सांगली ।
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) का कार्यालय, फोंडा, गोवा ।

[संख्या ई-11017/2/85-सी एल टी]
भवानी सिंह मीना, उप सचिव

New Delhi, the 19th August, 1985

S.O. 4173.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi, namely :—

1. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Poona.
2. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Nagpur.
3. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Chanderpur.
4. Assistant Labour Commissioner (Central)'s Office, Basco.
5. Labour Enforcement Officer (Central)'s Office, Bhusawal.
6. Labour Enforcement Officer (Central)'s Office, Sangli.
7. Labour Enforcement Officer (Central)'s Office, Phonda GOA.

[F. No. E-11017/2/85-C.L.T.]
B. S. MEENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

का०आ० 4174.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पी एण्ड टी सीनियर सुपरिंटेंडेन्ट आफ पोस्ट आफिसेज आगरा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 20th August, 1985

S.O. 4174.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of P and T through Senior Supdt. of Post Offices Agra, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 72/84

In the matter of dispute between :

Shri Surendra Kumar Srivastava S/o Shri Ravindra Pal Srivastava 14/219 Mani Sayeed Khan, Agra.

Versus

Senior Superintendent of Post Offices, Agra Circle, Agra.

APPEARANCES :

Shri R. D. Aggarwal—for the Management.
None—for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 31-10-84 vide Order No. L-40012(9)/84-D.II (B) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Senior Superintendent of Post Offices Agra Circle, Agra in terminating the services of Shri Surendra Kumar Srivastava, Wireman, Agra Fort, Head Post Office with effect from 2-1-82 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Notices were sent to the parties and the claimant appeared on 20-4-85 and sought a date for filing claim statement which was allowed to him for 18-5-85 but thereafter he became absent and has not appeared despite notice sent to him by registered post. He has been proceeded against exparte.

3 The Management explained that the workman S. K. Srivastava was engaged as outsider C. P. Wireman vice Raghubir Singh who had resigned from the post w.e.f. 24-8-79 purely on daily wages and was paid from contingencies and he was never sponsored by Employment Exchange nor were names called from Employment Exchange.

4. There was a complaint about the Tube Well not functioning and the motor had gone out of order and a preliminary enquiry was made believing S. K Srivastava to be at fault and the Department incurring loss of Rs. 425 for repairs of the motor. Ultimately the Management did not employ him further after 2-1-82.

5. In the circumstances aforesaid, the workman does not seem to have had any regular post being employed on contingency without names being called from Employment Exchange in a Government Department and, therefore, prima facie does not have a case for interference by this Tribunal and the Management action prima facie does not appear to be unjustified and the Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated : August 5, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-40012(9)/84-D.II (B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

का. आ. 4175—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कैन्टोमेन्ट बोर्ड, आगरा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4175.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantt. Board, Agra and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

I.D. No. 218|83

In the matter of dispute between :

The General Secretary, Cantonment Board Employees Union (INTUC), 2/236 Namnair-Agra.

AND

The Executive Officer, Cantonment Board, Agra.

APPEARANCES :

Shri Surendra Singh—for the workman &

Shri M. P. Khanna—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its notification No. L-13011|3|82-D.II(B) dated 15-7-83 has referred the following dispute for adjudication ;

"Whether the action of the management of Cantonment Board Agra in not absorbing their daily wages employees and granting them the benefits of permanent employees is fair, just and legal ? If not, to what relief the workmen concerned entitled ?"

2. On the first hearing one Shri N. Anandan as Secretary Cantonment Board Employees Union Agra moved an application that the parties are negotiating settlement which is under way and will be filed earliest so adjournment be granted, and thus the court granted adjournment and the parties reached on settlement which settlement is signed by President, Secretary of the Employees Union Cantonment Board Agra and the Cantonment Executive Officer on behalf of the cantonment Employer Agra. Agreement filed is annexure B that the cantonment board will re-appoint 17 retrenchment daily rated workers in the following manner that first six will be absorbed in 6 posts and another six will be appointed in Head E-9 after receipt of the sanction and they will continue to year to year basis and remaining 5 persons will be appointed in regular scale for 4 months. On the basis of this agreement an award was sent by my learned predecessor on 9th September, 83 for publication, but mean while Shri Surender Singh General Secretary INTUC moved an application that the award was obtained on the basis of false statement and the office bearers of the union mentioned therein were no more office bearers of the employees union Agra and that the reference was of a general nature and not regarding 17 workers. It was requested that the award be set aside. A notice was issued to the management but none appeared. On the evidence given by union representative Shri Surender Singh, the court ordered that the award made by Tribunal on 9-9-83 is set aside and the proceeding will be continued in this industrial dispute and the workman may lead his evidence in support of his contention. This order is dated 14th May, 84 and is on record. There was again a contest between rival unions alleging that the review application be rejected and award dated 9-9-83 be sent for publication. In the end the management moved an application on 8-4-85 alongwith photo copy received from the government stating that subsequent to the reference made and during the pendency of the case the Ministry of Defence, Government of India has issued an order dated 28-2-85, photocopy of which file) and that in view of this order the dispute raised by employees as per reference order dated 7-9-83 is stand reserved and the reference becomes infructous now, consequently the adjudication proceedings too are not proper. The government order shows that in relaxation of rule 5(B)(i) of the Cantt Fund Servants Rule 1947, I am directed to convey the sanction of the president to the regularisation of the canntt board employees w.e.f. from the date shown against each in annexure (i) and (ii) to this letter The annexure includes 16 names and it contains list of 16 persons including that of Shri Usman, Ayoob and Ashok Kumar their designation is also mentioned and different dates of appoint against them are mentioned. On 23-4-85, the mangement and workman's representative agreed that the award be given in terms of government letter submitted by the employer.

3. I accordingly give my award in terms of the letter of the Ministry of Defence, Government of India giving 16 daily wages casual employees regular appointment with the dates mentioned against them in permanent vacancies and also on the post mentioned as their designation.

4. I, therefore give my award accordingly.

5. Let 6 copies of the award be sent to the government for publication.

Dated : 2nd August, 1985

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

[No. L-13011(3)|82-D.II(B)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ. 4176—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एयर इण्डिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है ।

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4176.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air India and their workmen.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

Reference No. CGIT-3 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to Air-India, Nariman Point.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the workmen—Mr. Dighe, representative

For the employer—Mr. Verma, Advocate.

INDUSTRY : Airlines STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 21st day of June, 1985

AWARD

This is a reference relating to the action of the management of Air-India in respect of 34 casual workmen whose names are listed in the schedule. The issue referred is whether the action of the management "in not reinstating the 34 casual workers" is justified and "if not, to what relief the workmen are entitled?" I will briefly refer to the statement of claim and the written statement filed by the employees and the employer.

2. It is common ground that the action in question was taken on 18th January, 1982, meaning thereby that these workmen who were previously employed as casual workmen were not employed again. The contention of the workmen is that this action amounts to retrenchment of these workmen, without following rules laid down for the purposes of retrenchment, without assigning any reason, without notice and without paying retrenchment compensation. The claim statement, therefore, in short is that these 34 workmen were retrenched on 18th January, 1982 without showing any reason and without notice and without payment of retrenchment compensation. Their non-continuation of service amounts to dismissal without payment of retrenchment compensation and therefore, bad in law, the workmen having acquired the status of continuos workmen within the meaning of Section 25(f).

3. The management's contention is that the workmen were engaged as casual labourers and were not workmen within the purview of the Air-India Employees Service Regulations. As they were casual employees, there was no question of termination and there was no contract of employment between them. Hence, according to the employer, the demand for reinstatement is illegal. In other words, according to the employer, the scheduled workmen were not workmen at all and were only casual workmen engaged as and when required and necessary. They can not be deemed to have acquired the status of continuous employees, so as to attract the provisions of Section 25(f) of the Industrial Disputes Act. It denied that these workmen were retrenched or can be called to be retrenched. According to the Service Regulations of the Air-India employees, there are certain categories of workmen, such as permanent, temporary, probationers and substitutes. There is no category of casual workmen as contemplated by the regulations, and therefore, it is contended that there was no employer-employee relationship between the Corporation and these employees. Therefore, they are not entitled to any retrenchment compensation or notice pay. The Corporation also denied that these scheduled workmen had put in 240 days in a year. Their employment is on a day-to-day basis and is not of a continuous nature. Their employment depends upon the exigencies of work and is not for work which is of a permanent nature. The workmen are of unspecified categories.

4. Besides, these contention, it is the also the contention of the Corporation that "there is no industrial dispute as defined under section 2(k) of Industrial Disputes Act, 1947" existing between the Corporation and its workmen and the Reference as such is bad in law and not maintainable. At the time of the arguments, it was however contended that what the Corporation means is that there is no dispute between its 20,000 workmen who are represented by its 20 unions and the management. The 34 workmen whose case was espoused by the present union, called Airlines Employees Union, does not have any membership amongst the Corporation's what may be said to be accredited workmen, and therefore is not entitled to raise the present dispute. I have already referred to the other contentions that the scheduled employees are not its workers. Therefore, it was urged for both the reasons, namely, that the scheduled workmen are not workers and the representative union is not a representative union and has no membership amongst the accredited workmen and therefore the reference is not maintainable.

5. As regards this last contention, it must be mentioned that with regard to the question whether the Airlines Employees Union has no representation amongst the existing or accredited workmen of Air-India is a question of fact. The Corporation has not raised it in its written statement and therefore, the union could not have been called upon to answer. Nor is it a question which can be gone into as a purely legal question. The question whether the concerned union has a membership among other workmen is a question of fact. This factual foundation must be laid before any legal argument can be raised thereon. This contention therefore, can not be considered. What remains therefore is the only question with regard to these 34 workmen and whether the action in their behalf is justified or otherwise.

6. The matter was first argued in part on 17th of December, 1984 and an order came to be passed on that date. According to the workmen, these workmen were employed from 1977 onwards, though there was no evidence whatsoever to show that they had completed 240 days in a year or that they were employed from 1977. For the employer, it was stated that these were casual workmen not borne in any muster roll nor any pay-sheets were maintained for them. They were paid on vouchers. In that view, the employer was directed to produce vouchers; vouchers relating to each workmen showing the dates on which he worked and for which he was paid during the years 1977 to 1982. Subsequently, another order was passed on the 20th of January 1985 which would go to show that the employees were directed to file a statement "showing which of the workman was working continuously or was working discontinuously for which period and months year by year." The parties took time either to produce vouchers or to produce records and ultimately on behalf of the corporation, the learned counsel on 15th April, 1985 states that pay-sheets for the year 1981-82 are only available. Earlier pay-sheets are not available. That for the concerned workmen, all the pay-sheets which were available are produced and that no other document can be produced or are available. The union was, therefore, directed to inspect these vouchers and see whether the signatures of the concerned workmen are correct and theirs and whether they were paid accordingly and then file a statement. Another order came to be passed on 30th of April 1985, by which the Corporation was directed to produce muster rolls, if any and the pay-sheets for 12 months of 1981-82. In view of the fact that earlier records were not available that is more relevant order. Thereafter, inspection was allowed and taken by the union representatives of the record which was available with the Air-India. The union then produced on 12th of June, 1985, a statement showing the number of days the workmen have worked in between the period 19th January, 1981 to 18th of January, 1982. Which is the period which has to be taken into account for purposes of Section 25(f) and Section 25(b) of the Industrial Disputes Act. That is with annexure-A to the application of that date.

7. Of the 34 scheduled workmen, it is common ground that S. P. Jadhav at Sl. No. 18 and N.A. Karkera at Sl. No. 24 are no more concerned with the dispute. They have already been appointed and regularly employed by the Air-India Corporation and their case is not pressed. At a later stage, the union also gave up its claim with regard to 13 more workmen and confined its case only to 21 persons whose names are mentioned in the annexure to the application dated 12th June, 1985. Thus, it is the case of these 21 workmen alone which now survives for consideration.

8. The matter was posted for evidence and evidence was to be recorded today, when a statement was made by the employers and the employees to the effect that out of the statement filed by the union, six people at Sl. No. 9, 10, 12, 17, 19 and 21 have even according to the Corporation completed 240 days in a year preceding 18th January 1982. The Corporation conceded therefore, that their claim falls within S. 25(b).

9. It was contended for the Corporation that Sl. No. 13, 14 and 18 in the Annexure A, do not figure in the schedule of reference. That position is not disputed. There is no dispute that the name of some T.W. Bansode at Sl. No. 18 in annexure A to the application dated 12th June, 1984 does not figure at all amongst the names appointed to the reference in Schedule. So far as the other two are concerned, who are at Sl. No. 13 and 14 in the Annexure-A, their names are given as 'O.M. Sawant' and 'S. P. Kosole' in the schedule to the reference. The union contends that there is a mistake

in printing or typing, and persons at Sl. No. 30 and 32 are D. M. Sawant and S. V. Kasole and are the same persons. Its further contention is that I should make an order with regard to D M. Sawant and S. V. Kasole also, as they worked for 240 days in a year prior to 1982. I am afraid that this contention can not be accepted. I have no power to substitute in place of O.M. Sawant one D. M. Sawant and in place of S. P. Kasole, one S. V. Kasole. If correct names are not given in the order of reference and the Schedule, it was for the union to get the schedule amended by suitable action. As long as the schedule remains as it is, I have to treat the concerned workmen as O. M. Sawant and S. P. Kasole which do not figure in the statement at annexure-A. Threfore, the cases of workmen at Sl. No. 30 and 32 in the schedule of reference will also have to be droppped. That leaves the case of 4 more workmen only.

10. It is contended for the union that 10 workmen in annexure-A at Sl. No. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20 and 21 have completed 240 days of working and therefore are entitled to protection under Section 25(f), 25(b) and Section 2(oo) of Industrial Disputes Act. Of these, as I have already pointed out, it is admitted by the Corporation that persons at Sl. No. 9, 10, 12, 17, 19 and 21 have completed 240 days. Therefore what remains to be examined is the cases of workmen at Sl. No. 3, 5, 7 and 20 of the Annexure, for consideration as to whether they have completed 240 days.

11. A reference in this connection may be made to Section 25(B) which defines what is mean by continuous service. Of this sub-section, clause (2)(a) with which we are concerned reads as under :

"(2) Where a workmen is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous under an employer—

(a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—

(i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in mine; and

(ii) two hundred and forty days, in any other case."

12. It is clear therefore, that what has to be seen is the number of days these workmen had actually worked in a period "of 12 calendar months preceding the date" with reference to which this perod has to be counted. As the date in this case is 18th of January, 1982, preceding 12 calendar months will have to be taken into account and considered. According to Mr. Verma, learned counsel for the Corporation the calculation made by the union is for 13 months, since it took January, 1981 to January, 1982 into account. That seems to be as a result of misreading. What has been done perhaps and it was also clarified during the arguments, that the period was calculated from 18th January, 1982 backwards up to 19th January, 1981. The heading of the statement clearly goes to say that what has been taken into account is the period from 19-1-1981 to 18-1-1982. This statement is not disputed so far as its correctness is concerned and that could not have been disputed as it is a compilation from the Corporation's own record. In the circumstances, Mr. Verma learned counsel for the Corporation, subject to his contention, which I shall presently refer admits that these persons also completed 240 days, if the period accounted is from 19-1-1981 to 18-1-1982.

13. The learned counsel for the Corporation contended that the term 12 calendar months preceding the date has to be considered as 365 days. According to him, that contention finds support in certain settled judicial decisions. He was however, not able to cite any immediately. However, I find that the period considered for purposes of operation of Section 25(b) according to the Supreme Court is 12 calendar months, as held in Sur Enamal and Stamping Works Ltd. v. Their workmen (1963-II LLJ p. 367). The normal and natural meaning of the expression '12 calendar months preceding the date' would mean really the 12 calendar months which had preceded the date in question and the month in which that date falls, will have to be left out. By way of illustration for the present case, in my view the month of January may have to be left out and the period calculated from 1st January, 1981 to 31st December, 1981 which are the 12 preceding calendar months. In that view of the matter the case of these workmen would still become stronger. In view, however of the fact that the completion of 240 days it is stated to be from 19th January, 1981 itself, calculating 365 days prior to 19th January, 1982, and is not disputed it seems to me clear that these three workmen are also entitled to benefit of Section 25(f).

14. Now, section 25(f) lays down that "no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—

(a) the workman has been given one months' notice in writing indicating the reason for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice:"

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of service;

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and

(c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette."

15. I have already held that these 10 workmen have already completed service for a period of one year. As mentioned in Section 25(f) read with Section 25(b), their termination would be deemed to be retrenchment. It is common ground that they have not been given notice or notice wages or any retrenchment compensation. Therefore, retrenchment or termination of service, of them is bad in law. Section 2(oo) defines what is a retrenchment and means "the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action..." The termination of the employees' services or discontinuation which amounts to Retrenchment, attracts the provisions of the three sections, i.e. Section 2(oo) Section 25(b) and Section 25(f). The retrenchment/termination is bad in law and the employees are entitled to be reinstated. Hence the Award. The ten employees whose names follow as annexure to this Award shall be reinstated within one month from the publication of the award.

16.The employees would be normally entitled to backwages from the date of termination. Unfortunately, the statement of claim has not made any claim in that behalf. As the issue has not been joined in the absence of a claim, it would not have been possible for the employers to show that the workmen were not employed during all these days or that they gainfully employed. In the absence of either of the contention in the written statement and in the absence of anything in evidence. I would not grant them any back wages, but grant them only a lumpsum compensation of an amount of Rs. 2,000 per person.

17. Award accordingly that workmen at Sr. No. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21 in annexure-A to application dated 12th June, 1985 (Sr. No. 6, 9, 15, 25, 27, 29, 22, 11, 26, 12 in the schedule) are directed to be reinstated wthin one month from the date of the publication of the award. The corporation is also directed to pay them a sum of Rs. 2,000 each.

ANNEXURE

Sl. No.	Name of the workmen	Sl. No. in the annexure-A to the application of union dt. 12-6-1984	Sl. No. in the schedule of reference order
1.	A.J. Sable	3	6
2.	V.J. Raul	5	9
3.	B.K. Moro	7	15
4.	C.B. Donde	9	25
5.	K.D. Pawar	10	27
6.	V. J. Das	12	29
7.	T.G. Savardekar	17	22
8.	S.T. Satam	19	11
9.	D.N. Ghadi	20	26
10.	P.B. Kaher	21	12

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-11011(2)|83-D.II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का०आ० 4177—मैसर्स जय श्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लाल द्वारा बिल्डिंग न्यू लिंक रोड, स्वामी राम तीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055 (डी० एल/2819) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन बीमा जीवन के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिस को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-3501/164/85 एस० एस० 4]

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O. 4177.—Whereas Messrs Jay Shree Tea and Industries Limited, Lal Dwara Building, New Link Road, Swami Ram Tirath Nagar, New Delhi-110055 (DL/2819) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(184)/85-SS.IV]

का. आ. 4178.—मैसर्स महाराष्ट्र एपेक्स कारपोरेशन लिमिटेड, सिण्डिकेट हाऊस, पो० बाक्स नं० 38, मनीपाल-576119, कर्नाटक (कर्नाटक/4470 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों/संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिकवारिसों को जो यदि यह छूट, न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/177/85-एस.एस.-4]

S.O. 4178.—Whereas Messrs Maharashtra Apex Corporation Limited, Syndicate House, P.B. No. 38, Manipal-576119, Karnataka (KN/4470) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULF

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/177/85-S.S.IV]

का. आ. 4179.—मैसर्स युनाइटेड शिपर्स एण्ड ईजर्ज लिमिटेड, 67/2, लावेला रोड, बंगलौर (के. एन./5599) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों से समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवंश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/188/85-एस. एस.-4]

S.O. 4179.—Whereas Messrs United Shippers and Dredgers Limited, 67/2 Lavella Road, Bangalore (KN/5599) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/188/85-SS.IV]

का०आ० 4180.—मैसर्स ट्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जीवल प्रकाश, विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश/5965) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं:

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/191/85-एस०एस०-4]

S.O. 4180.—Whereas Messrs Dredging Corporation of India Limited, Jeevan Prakash, Vishakhapatnam (AP|5965) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish-

ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/191/85-SS.IV]

का. आ. 4181.—मैसर्स आर. जी. इस्पात लिमिटेड, प्लॉट नं. 9, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राजस्थान/2328) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फ़ायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधि वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/186/85-एस. एस-4]

S.O. 4181.—Whereas Messrs R.G. Ispat Limited, Road No. 9. Vishwakarma Industrial Area, Jaipur, (RJ/2328) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/186/85-SS.IV]

का. आ. 4182 :—मैसर्स इंटरनेशनल क्रेडिट एण्ड डेवलपमेंट सिंडीकेट लि., मनीपाल, डी. कन्नाडा, कर्नाटक-576119 (के. एन./6966), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/181/85-एस. एस.-4]

S.O. 4182.—Whereas Messrs International Credit and Development Syndicate Limited, Manipal, D. Kannada, Karnataka-576119 (KN|69663 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall imediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employeees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(181)/85-SS.IV]

का. आ. 4183.—मैसर्स नोक्टे टिम्बर कम्पनी लिमिटेड, डा. डिओमली, अरुणाचल प्रदेश (ए. एस./481), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गोहाटी को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत कियाजाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गौहाटी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उक्त राशि का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35011/182/85-एस. एस.-4]

S.O. 4183.—Whereas Messrs Nocte Timber Company Limited, P. O. Deomali, Arunachal Pradesh (AS/481) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gauhati maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall imediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gauhati and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(182)/85-SS.IV]

का. आ. 4184 :—मैसर्स मद्रास एलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड, मेट्टूर डेम, सलेम जिला (टी. एन./5324), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (ख) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/189/85-एस.एस.-4]

S.O. 4184.—Whereas Messrs The Madras Aluminum Company Limited, Mettur Dam, Salem District (TN/5324) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employeees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S-35014(189)/85-SS.IV]

का. आ. 4185 :—मैसर्स अतुल ग्लास एण्ड इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, 14/1 मथुरा रोड, फरीदाबाद (पी. एन./1465), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया

जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/183/85-एस. एस.-4]

698 GI/85—11

S.O. 4185.—Whereas Messrs Atul Glass and Industries (Private) Limited, 14/I, Mathura Road, Faridabad (PN/1465) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be les than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(183)/85-SS-IV]

का. आ. 4186 :—मैसर्स बड़ौदा जिला को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, बड़ौदा डेयरी, (गुजरात/4856), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/187/85-एस. एस.-4]

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4186.—Whereas Messrs Baroda District Co-operative Milk Producer's Union Limited, Baroda Dairy, Baroda-9 (GJ/4856) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir[nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014/187/85-SS.IV]

का. आ. 4187 :—मैसर्स सूरत जिला को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, सुमैल डेयरी, सूरत (गुजरात/2269) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[No. 35014(190)/85-SS-IV]

S.O. 4187.—Whereas Messrs Surat District Co-operative Milk Producer's Union Limited, Sumul Dairy, Surat (GJ|2269) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Sheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014/190/85-SS.IV]

का. आ. 4188.—मैसर्स कोयर-फोम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 14/10, मथुरा रोड, फरीदाबाद (पी. एन.-5598) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014(178)/85-एस.एस. 4]

S.O. 4188.—Whereas Messrs Coirfoam (India) Private Limited, 14/6, Mathura Road, Faridabad-121002 (Haryana) (PN-5598) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees

than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if one the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the permium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/178/85-SS. IV]

का. आ. 4189.—मैसर्स जनरल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, 26-ए, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल-मध्य प्रदेश (म. प्र./2049) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (2952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया

जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, यदि वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर को दराकर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस. 35011/180/85 एस. एस. 4]

S.O. 4189.—Whereas Messrs General Engineering Industries, 26-A, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal (MP) (MP/20491) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/1921/85-SS-IV]

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 4190.—मैसर्स कोयर-फोम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 14/6, मथुरा रोड, (पी. एल./5598) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस. 35014/176/85 एस. एस. 4]

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4190.—Whereas Messrs. The Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Raipur, Madhya Pradesh (MP/1135) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section17

of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/176/85-SS-IV]

का. आ. 4191.—मैसर्स आटो ग्लाइड प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 64, सेक्टर-6, फरीदाबाद (हरियाणा/9592) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां पेश करेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो; नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014/180/85-एस.एस. 4]

S.O. 4191.—Whereas Messrs. Auto Glide Private Limited, Plot No. 64, Sector-6, Faridabad (HR/9592) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2-A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the mapority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

No s 35014/180/85 SS IV]

का. आ. 4102.—मैसर्ज भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, 15/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) (पी.एन./3634) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एफ 35014/179/85 एस० एस०]

S.O. 4192.—Whereas Messrs, Bharat Foam Udyog Private Limited, 15|4, Mathura Road, Faridabad-121002 (PN|3654), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellenous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme by less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/179/85-SS. II]

का. आ. 4193.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरोड़ा फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीज 82, रिपन स्ट्रीट, जी. पी. ओ. बाक्स 2558, कलकत्ता-16 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35017 (80)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4193.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Arora Pharmaceutical Industries 82, Ripon Street, GPO Box 2558, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(80)/85-SS-II]

का. आ. 4194.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कालीदास मुलिक सेवायतन, 47, गणेश चन्द्र एवन्यू, कलकत्ता-13 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35017(79)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4194.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kalidas Mullick Sebayatan, 47, Ganesh Chander Avenue, Calcutta-13 have

agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(79)/85-SS-II]

का. आ. 4195.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फोना रबड़ प्रा. लि., 77, क्रिस्टोफर रोड, कलकत्ता-46 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करते हैं।

[सं. एम.-35017(81)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4195.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estabilshment known as Messrs Fona Rubber Private Ltd., 77, Christopher Road, Calcutta-46 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made aplicable to the said estabilshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(81)/85-SS-II]

का. आ. 4196.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कमर्शियल प्रोडैक्ट्स लि., स्टैंडर्ड इन्डस्ट्रियल ईस्टेट, पोस्ट आफिस टीटागढ़, 24-परगना और (रजि. आफिस), 95 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम.-35017(82)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4196.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Commercial products Ltd., Standard Industriar Estate, P.O. Titagarh 24-Parganas including its regd. Office at 95 Park Street, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said estabilshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(82)/85-SS-II]

का. आ. 4197.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बैनी पोलिमर्स, 56, टोपसिया रोड, (साउथ) कलकत्ता-46, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एफ.-35017(83)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4197.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bani Polymers 56, Topsia Road (South), Calcutta-46 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(83)/85-SS-II]

का. आ. 4198.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्डियन केन प्रा. लि; विलेज नारासिंघापुर, पोस्ट आफिस छोटो जागलिया, बड़सा जि.-24-परगना और (रजि. आफिस) 6, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-71 में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35017(84)/85एस. एस.-2]

S.O. 4198.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Indian Can Ltd. Village Narasinghapur P.O. Chhoto Jagulia Barasat, Dist. 24-Parganas, including its Regd. office at 6, Middleton Street, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(84)/85-SS-II]

का. आ. 4199.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है मैसर्स आना रबड़ इन्डस्ट्रीज, 56, टोपसिया रोड (साउथ), कलकत्ता-46 और 1, मेरेडिथ स्ट्रीट, कलकत्ता-72, में स्थित आफिस नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(85)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4199.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bani Rubber Industries 56, Topsia Road (South), Calcutta-46 and its office 1, Meredith Street, Calcutta-72 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(85)/85-SS-II]

का. आ. 4199.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बेनी रबर इण्डस्ट्रीज 56, टोपसिया रोड, फर्स्ट लेन, एगमोर, मद्रास-600008 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(328)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4200.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Devi Machine Tools Private Limited, 59, Pantheon Road, 1st Lane Egmore, Madras-600008, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(328)/85-SS-II]

का. आ. 4201.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवयुगा पिक्चर्स, गुनटाकल, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(330) 85-एस-एस-]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 4201.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Navayuga Pictures Guntakal, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(330)/85-SS-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

का०आ० 4202.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 4) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि० की जीलगोरा कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-8-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4202.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., At and Post Office, Jealgora, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 57 of 1982

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.
On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S., Dhanbad.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 9th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(28)/82-D.III (A), dated, the 19th May, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Jealgora Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, At and P.O. Jealgora, District Dhanbad that Shrimati Jaya Devi should be regularised on the post of Cartridge Maker in Category-I as per National Coal Wage Agreement is justified ? If so, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned work lady Smt. Jayadevi was appointed as Wagon Loader in 1972. She was confirmed as Wagon Loader. In the year 1978 she was engaged by the management of Jealgora Colliery on the job of Clay Cartridge Maker along with a gang of other similar workers. The other workers who were engaged as Clay Cartridge Makers are all paid time rated Cat. I plus other benefits available to a colliery worker but the concerned lady was paid a consolidated wage of Rs. 15 per day without paying any other benefit. The management has taken a different stand in case of the work lady and thereby she has been discriminated with other workmen doing the

same type of job. When she had worked for sufficiently long period she represented her case before the management and the union of workmen also made a written representation but the management did not pay any heed. Thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC (C) Dhanbad who took up the matter with the management and held conciliation proceeding which ended in failure and thereafter the Ministry of Labour referred the present reference before this Tribunal for adjudication. It is submitted that the management has discriminated by not paying the concerned work lady the same rate of wages and allowances as have been paid to other workmen employed on the same job and as such the demand of the workmen is justified and she should be paid wages and allowances etc. in time rated cat. I as have been paid to all other similar workmen from the date of joining the duty in 1978 with all consequential effects and other relief.

The case of the management is that the concerned work lady was a confirmed wagon loader and was continuing as such. As her substantive appointment was to the post of Wagon Loader she had no right to claim for the post of Clay cartridge maker. The concerned work lady approached the management to give her employment as Clay cartridge maidoor in Cat. I for a temporary period to tide over her difficulties and thereafter she was employed as Clay cartridge maker. The job of making clay cartridge is a light job given to workmen on account of health reasons and to overcome certain personnel difficulties. The workmen given light job to overcome his difficulties is to resume her original duties as soon as the difficulties are over and the workmen cannot insist to continue in the employment of the light duty although. When the concerned work lady was asked for resuming her original and substantive duty of wagon loader, she approached the union which raised the present dispute. The union is not justified in demanding for regularisation of the concerned work lady as clay cartridge maker.

Her employment as clay cartridge maker temporarily cannot entitle her for permanent absorption in that post. The concerned work lady will not be entitled to regularise as clay cartridge maker.

The only point for consideration in this case is whether the concerned work lady should be regularised in the post of Clay cartridge maker in Cat. I.

The workmen examined two witnesses and the management also examined one witness in support of their respective cases. The management has further produced documents which have been marked M-1 to M-9. It will appear from the evidence of WW-1 the concerned work lady herself and the evidence of WW-2 that she is working as clay cartridge maker and is getting wages of Rs. 15 per day. It will further appear that 6 other women employed along with her to work as clay cartridge makers were getting time rated Cat. I wages. WW-2 is one of the workmen working with the concerned work lady as Clay cartridge maker. She was also formerly working in another place as shale picker and thereafter she was transferred to work as Clay cartridge maker. Similarly the concerned work lady who was working as Wagon loader was transferred to work as Clay cartridge maker along with 6 others. It will appear from the evidence of MW-1 that the concerned work lady is entitled to get the wages of time rated Cat. I since she was employed to work as Clay cartridge makers. Thus it will appear that now there is no controversy whether the concerned work lady who is working as clay cartridge maker is entitled to the time rated wages of Cat. I since her employment in the job of Clay cartridge maker.

The management is not insisting now for sending her back as a wagon loader. The concerned work lady has worked admittedly as clay cartridge maker since 1978 till now and as such she deserves to be regularised as a clay cartridge maker in time rated Cat. I. The management has filed some wage sheets to show the actual amount of payment made to the concerned work lady for some period. It will appear from NCWA-I which was applicable from 1-1-75 that the basic wages of Cat. I daily rated worker was fixed @ Rs. 10 to 12. The concerned work lady was employed to work as clay cartridge maker in 1978 and as such she was entitled to this rate of wages till NCWA-II came into force from 1-1-79. According to NCWA-II the wages of daily rated Cat. I workmen was raised from Rs. 10 per day in the scale of Rs. 15.00-0.26-18.12 and as such the concerned work lady was entitled to the revised pay scale of Rs. 15.00-0.26-18.12 P. per day from 1-1-79 to 1-1-83 when NCWA-III came into force. According to NCWA-III which came into force from 1-1-83 the wages of daily rated Cat. I workmen was revised to Rs. 21.16-0.43-27.18 P. The concerned work lady is not in possession of papers to show the amount of wages which was actually received by her and the said account are with the management. The management therefore will account for the amount which she is entitled to receive in accordance with the scale of wages stated above and after making deduction of the amount which has already been paid to her, the balance which remain to be paid must also be paid to her. In this connection I may mention that I have only stated about the basic wages which she was entitled under the different awards of NCWA. She is also entitled to the other benefits available to a Cat I time rated worker and account has to be made in respect of those other benefits as well and the balance which has not been paid to her is to be paid at an early date.

In the result, it is held that the demand of the workmen of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. that the concerned work lady Srimati Jayadevi should be regularised on the post of Clay catridge maker in Cat. I as per NCWA is justified and the amount due must be paid to her after calculation as indicated above.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(28)/82-D.III (A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

का. आ. 4203.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4203.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial, Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

Industrial Dispute No. 243 of 1983

In the matter of dispute between :

Shri Suresh Chandra Upreti, 135/206, Bans Mandi Muttiganj, Allahabad. Workman.

Versus

The Regional Manager, Region III, State Bank of India, The Mall, Kanpur. Management.

APPEARANCE :

Shri Mangalwadekar, representative for the workman & Shri A. S. Saxena, representative for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/146/83-D. II A, dated 8th December, 1983, has referred the following dispute for adjudication;

Whether the section of the management of State Bank of India, Region III, Kanpur in relation to their University Branch, Allahabad in discharging from service Shri Suresh Chandra Upreti, Clerk with effect from 27-10-77 is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?

2. It is common ground that the workman Shri Suresh Chandra Upreti was a clerk in the management bank's branch of the University Branch, Allahabad, and that his appointment was made by Deputy Secretary and Treasurer of State Bank of India, at Kanpur, at the Allahabad Branch, on 31-12-70 and deputed at University Sub-Office on 4-1-1971, and that at the time of discharge from the service the workman was working in the management bank's University Branch, Allahabad and that the workman was getting total emoluments Rs. 720 plus Rs. 72 as salary and allowance excluding banks contribution towards Provident Fund and pension.

3. It is further admitted that the management bank is an industry. It is further admitted that on 13-12-76, the opposite party No. 2 i.e. Branch Manager issued a memo to the applicant regarding Saving Bank Account No. 6223, in the name of Smt. Pratima Sharma to which the applicant replied on 20-12-76. Thereafter, the applicant was suspended by the management on 22-12-76. It is further not denied that on 10th January, 77 Mrs. Sharma holder of saving banks a/c No. 6223 of bank's University Branch, Allahabad, wrote a letter to the management dated 10-1-77. According to the workman the letter was to the effect that the workman was not at all guilty to the charge of mistake with which the workman was charged. It was on 12-2-1977 that the workman was served with a charge sheet by the management to which the workman replied on 14-2-77. It is further admitted that one Shri G. S. Kapoor Officer Gr. I of the Allahabad Branch informed the applicant on 22-3-77, about the enquiry and completed the enquiry on 23-4-77 The workman has averred that in the enquiry he was not allowed opportunity to cross examine nor was heard. On 23-4-77 the workman submitted written arguments but despite all that he was discharged in terms of para 521(10)(c) of the Sastri Award, defined by para 18.20 of the Desai Award and thus the services of the workman were terminated w.e.f. 20-10-77, without giving a chance for hearing on the proposed punishment. It is not denied that the applicant requested the management vide letters dated 29-10-77 and 21-11-77, on the copy of the enquiry proceedings and the findings of the enquiry officer made thereon but the same was turned down by the management vide letter dated 5-12-77.

4. The management contention is that in view of initial admission of charges levelled against him and his plea of mercy, the workman was not required to furnish the documents required. It is further admitted that the workman submitted an appeal on 22-9-78. It is further admitted that the workman filed appeal dated 7-4-78, 15-11-79 and on 8-10-80 to the Chief Regional Manager, State Bank of India, Varanasi, which were not replied by the management as according to them there was no provision of the second appeal. The management has admitted that the applicant was suspended on 22-12-76 while the charge sheet was issued on 12-2-1977 was justified as the workman was suspended on pending enquiry. It is not specifically denied that alongwith charge-sheet copies of the documents and statements of service should have been supplied.

5. The workman has raised objection that the Enquiry Officer, was not competent authority and the appointment of the enquiry officer was illegal. In the end the workman has averred that the submissions made during the domestic enquiry were under duress and thus it can not be relied upon. It is consequently prayed that the termination order dated 25-10-77, be quashed and the workman be reinstated with continuity of service.

6. The management denied the admissions referred above and have averred that the workman was charge sheeted for having collected the amount from one Smt. Pratima Sharma account holder of S.B. A/c. No. 6223 and retaining it and misutilising the same unauthorisely and making false entries of the pass book of the account holder of S.B. A/c. No. 6223 and thereby falsely representing the factum of deposits to the bank. That vide letter dated 20-12-76 he made unclarified admission of his guilt and pleaded for pardon in the following words:

> That I committed a grave errors of judgment by not keeping in mind the implications and/or complications that might arise from my foregoing actions, and for that I take this opportunity Sir, to offer my profound apology and regret. Lastly Sir, I offer my unconditonal surrender and pray for your merciful pardon as a special case, and for this act of your benevolent charity, I shall ever remain grateful to your goodself, as well as the institution.

7. It is averred that in view of the mercy appeal the bank took lenient view as a special case and the workman was discharged from the bank not amounting to punishment under section 521(10)(c) of the Sastri Award.

8. The discharge letter filed by the workman is signed by Regional Manager I who is disciplinary authority. In this he has observed that considering the enquiry proceedings and findings of the Enquiry Officer, the punishment warranted dismissal from the service, but having regard to the young age of the workman, the disciplinary authority decided to condone the mistake and simply to discharge the workman from service, which discharge was under para 521 (10)(c) of the Sastri Award which reads as follows;

> In awarding punishment by way of disciplinary action the authority concerned shall take in to account the gravity of the misconduct, the previous record, if any, of the employee and any other aggravating or extenuating circumstances that may exist. Where sufficiently extenuating circumstances exist the misconduct may be condoned and in case such misconduct is of the gross type he may be merely discharged, with or without notice or on payment of a month's pay and allowances, in lieu of notice. Such discharge may also be given where the evidence is found to be insufficient to sustain the charge and where the bank does not for some reason or other, think it expedient to retain the employee in question any longer in service discharge in such cases shall not be deemed to disciplinary action.

9 Thus this discharge was by way of punishment though mentioned as discharge in view of provision of para 521(10)(c) of Sastri Award as the management did not consider it proper to retain the employee any longer in its service and passed the order of discharge which was to be deemed not amounting to punishment.

10. In the rejoinder the workman took plea that discharge simpliciter being retrenchment section 25F were not complied whith, hence, order of the discharge is violative and he deserves to be reinstated in service with full back wages.

11. Despite the fact that the account holder Smt. Pratima Sharma gave letter ext.M-3 dated 10.12.76 that she had received Rs. 550.72 paisa from Shri Upreti the discrepancy of between the pass book and ledger and authenticated entries in the pass book by workman himself could not be reconcilied and it was in these circumstances that the workman admitted his guilt. Even if discharge from service on 15th October, 77 the workman on 22.9.78. filed his mercy appeal which is admitted by him. In the said mercy appeal workman admitted that having almost family relations, he always extended her facility which was never ill intended but was contrary to the rules of the bank and that whatever transactions were there in that account were never by way of any gain to the applicant or by any loss to her. He has further admitted that some entries confirming with the ledger were made in her pass book in good confidence as an arrangement of conveyance to her and that the mistake by him innocently came to the notice of the Branch Manager when the pass

book of Smt. P. Sharma account holder of SB A/c 6225 some entries were found not in conformity with the ledger account.

12. In view of the above admissions and despite the fact that account holder Smt. P. Sharma wanted that the workmen be exonerated and despite the fact that in view that the termination was not effected by the management the workman blame himself in view of the admissions and the discharge order was rightly passed by the management in view of provision of section 52(10)(c) of the Sastri Award.

13. The only mistake committed by the management was not taking the note that the termination for any reason whatsoever, the point be considered is whether the dicharge from service would be retrenchment within the meaning of section 2(oo) of the I.D. Act. If the discharge is by way of punishment inflicted by way of disciplinary action it would be retrenchment. Termination order reads as follows;

> The papers have been examined by me. In view of the clear admission of guilty by Shri S. C. Upreti the final punishment of dismissal as envisaged in the case involving fraudulent entries in the bank's books as also the pass books of the depositor should be inflicted. However, in view of the unblemished service record as also complete surrender made by the employee as also the fact that he is a young and up coming employee, the extreme penalty by way of dismissal is not being imposed on the merits of the case so that avenues for rehabilitation of the employee still remain open. He is accordingly discharged from the Bank's service.

The order of discharge is by way of punishment though in place of extreme penalty of dismissal so that avanues for rehabilitation of the employees still remain open. Thus even section 25F also has not been violated by the management nor a question of giving charge sheet notice or one months notice or retrenchment compensation is required

14. Now coming to the point whether discharge order was passed by an officer not to competent to pass that order. The workman alongwith his affidavit has filed annexure I the photo copy of the appointment letter dated 13-12-70 whereby as a result of interview held he was required to join duty latest by 31-12-70. The letter is signed by Deputy Secretary and Treasurer of the Kanpur Local Head Office of the management and the workman was terminated by the Regional Manager, Region No. II Kanpur. It is common ground that after service on 31-12-70, at Kanpur, the workman was transferred to Allahabad University Branch on 4-1-71. It has not been shown by the workman how Secretary and Treasurer of the management bank is higher in rank and the termination made by Regional Manager Region II Kanpur is lower in rank. The highest Officer in the region is General Manager and thereafter Chief Regional Manager and then Regional Manager. Dy. Secretary and Treasurer of the Kanpur Local Head Office, has not been shown to be lower in rank than the regional manager. The management witness Shri V. K. Mehrotra M.W.1 has deposed that Deputy Secretary and Treasurer is equivalent to the post of General Manager and Regional Manager is lower in rank to the Chief Regional Manager. There is no other post between General Manager and Chief Regional Manager. Thus according to the testimony of the management banks witness the termination has been made by an officer lower in rank than the person who had appointed him. Discharge or termination should not be by person lower in rank than the officer who appointed him. In the instant case admittedly a person lower in rank terminated the services of the workman and on that account the termination of the workman is illegal. Thus in view of the regulation 55 of the State Bank of India para (2)(a)(iv) lays down such officer or employees shall not be dismissed from service of S.B.I. by an authority lower than the appointing authority".

15. Thus in view of the discussion above, the discharge of the workman by person lower in authority is illegal The result is that the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.

16. On the point of delay it may be pointed out that there is no limitation for sending the reference for adjudication. Further it was in the wisdom of the Government to have refer the dispute for adjudication at any proper time, it desired so and it can not be said that the reference is invalid on account of delay.

17. In view of the reasons discussed above I hold that the action of the management of State Bank of India, Kanpur, in relation to their University Branch Allahabad in discharging Shri Suresh Chandra Upreti Clerk with effect from 27-10-77 is not justified

18. The result is that the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.

19. I, therefore, give my award accordingly.

20. Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/146/83-D. II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ. 4204—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चन्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O.4204.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CHANDIGARH

Case No. I. D. 18/1984

PARTIES :

Empolyers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their workman—Garibu Singh.

APPEARANCES :

For the Employer—S/Shri Mangoo Ram and V. K. Bansal

For the Workman—Shri P. K. Singla.

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 6th of August, 1985

The Central Government Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No. L-42012(9)/83-D.IV (B)/D.V. dated the 28th of May, 1984 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

> "Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Shri Garibu Singh, Watchman with effect from 2-3-82 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Brief facts of the case, according to the petitioner Workman, are that he was working as a Casual watchman under the Respdt. Corporation at their Dhuri Storage Depot since 1-5-1981 till 2-3-82 when he suddenly fell ill and could not attend duty for the next two months. It was complained that on 3-5-1983 when he returned to duty and produced a medical certificate, the management refused to entertain it and informed him that his services had already been terminated since 2-3-82. The petitioner assailed his termination on the ground that it was violative of the mandatory provisions of Section 25-F, 25-G, 25-H, and 25-N because he was deprived of all the terminal benefits. He, therefore, approached his Union and raised a demand for his reinstatement with full back wages. But the management was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage and hence the Reference.

3 Resisting the proceedings, the management justified their action on the plea that the petitioner had voluntarily abandoned his job without caring to inform them and that the entire story of his alleged illness was a fake, an after thought and sheer concoction. As a necessary corollary, they opposed his effort to seek any terminal benefits. On facts, despite an admission of the petitioner's casual engagement, they denied that he had completed 240 days of service in one year. It was rather explained that he had worked for them in two different spells from 1-5-1981 to 15-11-1981 and 21-12-1981 to 2-3-1982.

4 Keeping in view the comprehensive nature of the terms of Reference, the parties were called upon to adduce evidence in support of their respective versions without going through the drill of casting any formal issues. Thus the petitioner examined his authorised representative Shri P. K. Singla and filed a number of documents whereas the management felt contended with the deposition of their Asstt. Manager Shri Mangoo Ram. I have carefully gone through the entire available data and heard the parties.

5. The crucial point which requires determination in this case is as to whether or not there was voluntary abandonment of job by the petitioner, because in the light of Management's own pleadings in para No. 2 of the written statement he appears to have been in continuous services for more than one year within the meaning of Section 25-B of the Act and it hardly requires any emphasis that disengagement of such like workman calls for a strict compliance of the provisions of Section 25-F, G and H.

6. On behalf of the petitioner my attention was drawn towards the documents Exts. W-4 and W-7 to W-10 with the submission that when the petitioner reported for duty on 3-5-1982 he had produced the medical certificate Ex. W-4 revealing that during the period of his absence he was bedridden due to Typhoid and that Ex. W-7 to W-10 were filed to impress that a similarly placed worker named Karamsingh was shown indulgence of reinstatement by the management. It was, therefore, argued that it was a clear case of flagrant discrimination.

7 Inspite of its seeming attraction the submission failed to carry conviction with me because it appears to relate more to the domain of surmises and conjuctures rather than facts. It may be worthwhile to mention here that no such plea was taken either in the Claim statement or the Rejoinder. So much so that it was not even projected in the affidavit Ex. W-1 of petitioner's representative Shri Singla. To put it in other words, the management got no opportunity to adduce evidence of fact or circumstances leading to the reinstatement of Karam Singh Otherwise also, a bare perusal of the petitioner's Medical certificate Ex W-4 would expose the hollowness of his claim. This document purports to have been issued by a Registered Medical Practitioner named Manohar Lal who neither cared to disclose his own address nor attestation thereon by the petitioner Ordinarly such type of certificates are issued for the patients who are kept under treatment on being entered in the "Patient-Register" But in this case no such norm was observed, as would be evident from the absence of any registration number on the document. And it hardly requires any emphasis that both of them i.e. the Doctors as well as the petitioner himself, who could have been the best witness of the incident of his alleged illness; opted to refrain from the witness box for no explicable reason. The inference is, therefore, obvious that they wanted to avoid exposure on the acid test of cross-examination. It is besides the point that even this Certificate Ext. W-4 issued ex post facto.

8. On the other hand from the documents Exts. W-8 to W-10 it appears that Karam Singh was bed ridden due to fractured leg when he approached Dr. O. P. Bansal of Sangrur i.e. the place where he was employed; he got himself registered with the Doctor on the very first day of his absence at Registration No 450 and in due course the fitness certificate was also issued to him. In a manner of speaking documents Ex W-9 and W-10 give prima facie indication that there was nothing doubious about his illness.

9. Be that as it may, in our case there is absolutely no explanaion as to how and why the petitioner failed to inform his Employer for more than two months regarding his alleged illness. Similarly there is no worthwhile evidence to show that on 3-5-1982, he had furnished his aforesaid medical certificate to any particular officer of the Corporation with a prayer to condone his absence. In my considered opinion, against such back-drop, the management had every logic to assume that he was no more interested in serving them and had abandoned his job voluntarily for the reasons batter known to him.

10 Hence in the totality of the circumstances, I find no impropriety in their action and, as such, return my Award against the petitioner/Workman.

Chandigarh,
6-8-1985

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012/9/83-D.IV (B)/D V.]

का. आ. 4205.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ब प्रोजेक्ट अधिकारी, टापिन साउथ कोलियरी मैं० सी० एल० के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-8-85 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 4205.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Central Government Industrial Tribunal No. 2, P.O. Jagjiwan Nagar, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management Project Office, Tapin South Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 4 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Setion 10(1)(d)

of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Project Officer, Tapin South Colliery of M/s. CCL and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 14th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(73)/84-D IV (B) dated the 18th January, 1985.

SCHEDULE

I. "Whether the stoppage of three annual increments of Shri Gurudayal Singh, Dumper Operator of Tapin South Colliery by the Project Officer (TSC), Tapin South Colliery of the Central Coalfields Ltd. is legal and justified ?"

II. "Whether the action of the Project Officer Tapin South Colliery in withholding 1/3rd of the wages of Shri Gurudayal Singh during his suspension period in addition to the stoppage of his three annual increments with cumulative effect is legal and justified ?"

III. "If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Gurudayal Singh was working as Dumper Operator at Tapin South Colliery of M/s. CCL. He was an active members of the Coalfields Labour Union since the year 1976. In the year 1977 and 1978 there was a serious rivalry between the Coalfields Labour Union and RCMS in which the concerned workman being staunch supporter of the Coalfield Labour Union took active part in the organisation of his union. The rival union made several attempts to win over the concerned workman so that he may desert Coalfield Labour union and he was allured for an accelerated promotion if he joins the rival union but he did not agree. Due to the trade union activities of the concerned workman the rival union could not take its root in the Tapin South Colliery. When the rival union failed to gain over the concerned workman they hatched up a plan with the connivance of the management of the Tapin South Colliery and thereby on false allegation chargesheet was submitted on the concerned workman on 22-11-78. The concerned workman was falsely charged for committing rape on Smt. Bitco Kamin wife of Ritlal Manjhi. A drama of domestic enquiry was enacted in which the members of the rival union who had been persuading the concerned workman to join the union deposed as management's witnesses before the Enquiry Committee. Not a single independent witness appeared in support of the charge against the concerned workman. The woman alleged to have been raped by the concerned workman was not an employee of CCL and the place where the alleged rape was committed was outside the leased area of Tapin South Colliery. The Enquiry Officer did not correctly record the statement of the witnesses of the Enquiry proceeding. Even the statements of Bitco Majhiain was not correctly recorded as the same Bitco Majhiain had flatly denied to have any know of the case when she deposed before the Sessions Court at Hazaribagh in the case of rape instituted against the concerned workman. She had deposed before the Sessions Judge that she was not raped and her husband Ritlal Manjhi has denied his knowledge about the alleged rape of his wife and accordingly the concerned workman was acquitted by the Second Additional Sessions Judge, Hazaribagh. The concerned workman had made a representation before the Project Officer that the enquiry Officer was biased and had wrongly recorded the statement of Bitco Majhiain under the pressure of S/Shri K. K. Bajpai, Maharan Keshri etc. The Project Officer ordered the Enquiry Officer to record the statement of Bitco Majhiain afresh and thereafter the Enquiry Officer took the statement of Bitco Majhiain on 14-4-79. Bitco Majhiain had admitted in cross-examination at that time that the concerned workman did not committ rape on her or take away her petty coat. It is submitted on behalf of the workman that the management should have withdrawn the charges levelled against the concerned workman after consideration of the affidavit of Smt. Bitco Majhiain made before the Court and her statement dated 14-4-79. The act of the management in stopping three annual increments with cumulative effect and withholding 1/3rd of his wages during the period of his suspension was an act of victimisation for the trade union activities of the concerned workman. The management had paid only 2/3rd of wages to the concerned workman during the entire period of his suspension and the remaining 1/3rd of his wages had not been paid to him even after the order of punishment notified on 1-1-79. It is prayed on behalf of the concerned workman that an Award be passed in his favour.

The case of the management is that on receipt of report of certain acts of misconduct stated to have been committed by the concerned workman and two other workers namely S/Shri Balmukund Singh, Dumper Operators and Jagdish Ram, Grader Operator of the same colliery were issued with a chargesheet dated 22-11-78 and were placed under suspension with effect from the said date pending enquiry into the charges framed against them. The charges framed against them were :—

(1) That on 19-11-78 at about 7.30 PM near the colliery dispensary of Tapin South Colliery, Shri Gurudayal Singh, Dumper Operator, Tapin South Colliery had forcibly snatched the transistor belonging to Shri Ratilal Manjhi, Piece rated worker of Tapin South Colliery. Shri Gurudayal Singh also assaulted Shri Ratilal Manjhi in the course of which Shri Gurudayal Singh tore up his shirt. Shri Gurudayal Singh further caught hold of Smt. Bitco wife of Shri Ratilal Manjhi, and forcibly dragged her to the side of the road although Smt. Bitco protested and struggled to get free from his clutches, Shri Gurudayal Singh forcibly laid her on the ground and violated her chastity by molesting her and by committing rape on her.

(2) That S/Shri Balmukund Singh, Dumper Operator, Tapin South Colliery and Jagdish Ram, Grader Operator, Tapin South Colliery were with Shri Gurudayal Singh at the above mentioned place during the time when the above acts were committed and had actively aided and abetted Shri Gurudayal Singh in the above acts.

The concerned workman was served with a chargesheet and thereafter he submitted his reply dated 12-12-78. His explanation was considered to be unsatisfactory by the Project Officer/Agent and thereafter a detailed enquiry was ordered by him and Shri B. N. Singh, Administrative Officer Tapin Colliery was appointed as Enquiry Officer. After due notice to the workman concerned the enquiry officer held the enquiry in accordance with the principles of natural justice and full opportunities were given to the concerned workman to defend himself. The management's witnesses were examined in his presence and was given an opportunity to cross-examine the management's witnesses. The workman also was given an opportunity to make his statement and to examine his witnesses in defence. After completing the enquiry the enquiry officer found the concerned workman guilty of having committed rape on Smt. Bitco wife of Ratilal Manjhi which was an act involving moral turpitude. The enquiry officer submitted his enquiry report on 27-2-79. Thereafter the concerned workman had submitted a copy of the affidavit purported to have been sworn by Smt. Bitco stating that she had made the allegation against Shri Gurudayal Singh and others at the instigation of Shri K. K. Bajpai and others. Thereafter the Project Officer with the approval of the General Manager, Hazaribagh Area advised the Enquiry Officer to interrogate Smt. Bitco in presence of the concerned workman and the same was done by the Enquiry Officer and the concerned workman was given an opportunity to cross-examine Smt. Bitco Kamin. The enquiry officer submitted a further report stating that Smt. Bitco had denied to have filed the affidavit in question. The Enquiry Officer had further stated in his report that Smt Bitco Kamin was enticed and in-

midaved by the concerned workman and others to ille a petition given contradictory statement by her and by her husband after the enquiry was over and the enquiry officer further reported that the findings given by him in his enquiry report dated 27-2-79 would stand. The Project Officer/ Agent, Tapin South Colliery considered the enquiry report and having agreed with it imposed the punishment of stoppage of three annual increments with cumulative effect by his order dated 1-5-79. The Project Officer also passed an order that the concerned workman will not be paid anything more than the substantive allowance already paid to him for the period of suspension pending enquiry. The concerned workman was allowed to resume duty from 2-5-79. It is submitted on behalf of the management that the stoppage of three anual increments of the concerned workman was fully justified and that the payment of only 2/3rd subsistence allwance for the period of suspension was also justified. It is prayed on behalf of the management that the Award be passed in their favour.

By order dated 21-6-85 this Tribunal has held that the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper. Thereafter the case was heard on merit and the entire proceeding before Enquiry Officer was gone into to see whether the charge was established against the concerned workman and whether the punishment inflicted upon him was just and proper.

Ext M-18 is the Enquiry Proceeding in which the statement of all the witnesses examined before the Enquiry Officer has been recorded and Ext. M-19 is the Enquiry report dated 27-2-79. It will appear that four witnesses were examined on behalf of the management out of whom Enquiry Officer did not place reliance of his evidence of Ratilal Manjhi as it was not convincing. MW-4 is the lady Smt. Bitko who was alleged to have been raped by the concerned workman. She had clearly stated that while she was coming along with her husband she met three persons in the way out of whom she could not identify two at that time who caught hold of her husband and the concerned workman whom she indentified dragged her towards the nearby jungle and committed rape on her. There is nothing in the enquiry proceeding Ext M-18 to show that Bitko had ever stated that the concerned workman had not committed rape on her person. Her evidence finds corroboration by the evidence of MW-2 Haridutt Awasthi and MW-3 Anwar Hussain who are also working as Dumper Operator. Both of them were coming together after making an enquiry whether there would be a cinema show or not and while coming in the way they found the concerned workman lying upon Bitko and her body was naked below her waish. It was about 7.30 in the evening and it had become dark but some dim light was coming at the spot from the hospital side. It is clear therefore from the evidence of Bitko and the evidence of MW-2 and MW-3 that the concerned workman had committed rape on the person of Smt. Bitko and that on arrival of these two witnesses the concerned workman fled away. The evidence of MW-2 and MW-3 has been criticised on the ground that they belong to the rival union and as such they were deposing against the concerned workman. In the earlier reply of the concerned workman to the chargesheet it had not been stated that Haridutt Awasthi and Anwar Hussain were having rivalry with the concerned workman. Ext M-2 is the reply to the chargesheet which was filed by the concerned workman. It was also after Haridutt Awasthi and Anwar Hussain gave their statement in the enquiry proceeding that the concerned workman started making allegations against them so much so that the concerned workman got examined defence witnesses alleging that Haridutt Awasthi was seen committing rape on Smt. Bitko and that Anwar Hussain was seen taking the transistor of Ratilal Manjhi. On this point of fact as is alleged in the statement of defence witnesses, there was no reason for Smt. Bitko not to make any allegation against Haridutt Awasthi and Anwar Hussain and instead making allegations of rape against the concerned workman. Moreover if the defence as has been alleged before the Enquiry Officer was true, the said fact must have been stated in Ext M-2, which was the earlier statement of the record in which the concerned workman could have stated that he had not committed rape but Haridutt Awasthi had committed the range on Smt. Bitko. Besides that there is no reason for Smt. Bitko to falsely implicate the concerned workman and to leave Haridutt Awasthi if he had really committed the rape.

Out of the witnesses examined in defence DW-1 Jagdish Ram, DW-2 Bal Mukund are the two personal against whom chargesheet had been submitted along with the concerned workman and as such it is quite natural that they are avoiding to admit the facts alleged in the chargesheet. DW-5 Kamaljit Kaur is the wife of the concerned workman Gurdayal Singh from whose mouth the story of rape of Bitko by Haridutt Awasthi has been alleged. Gurdayal Singh has also stated that on being reported by his wife he went out and saw rape being committed by Haridutt Awasthi on Smt. Bitko. As I have already stated above these facts appear to be clearly concocted just to have a defence as the said fact was not stated earlier in the reply to the chargesheet by the concerned workman or in the written statement of this case although the facts which are being alleged were known to them since before the filing of the reply by the concerned workman. DW-3 Balwant Singh stated that he was at the residence of Jagdish Ram along with Gurdayal Singh, Jaginder Singh and Lachman Singh on the alleged date and time of occurrence. DW-4 Shri Jainarain Singh was not present at the place of occurrence. Moti Majhi has stated that Anwar and Awasthi came to him at the Pump house and asked him to go and see and thereafter he went and found the wife of Ratilal Manjhi lying to the south of the female hospital. He had not seen the real occurrence, but in a way it supports the case of the management. Had Awasthi committed the rape on Smt. Bitko he would not have gone to Moti Manjhi to go and see wife of Rati Manjhi. Thus there were materials before the Enquiry Officer to show that the concerned workman had committed rape on the person of Smt. Bitko and on the basis of the statement made before him he submitted his enquiry report Ext. M-19 on 27-2-79. Till then there was nothing before him to show that Smt. Bitko was making varying statement denying the rape on her person by the concerned workman and as such if the matters which came subsequent to the filing of his report could not have been envisaged by him and as such the said enquiry report cannot be said to be vitiated for non consideration of the affidavit of Smt. Bitko or any statement made by her before the Sessions Court.

Ext. M-21 is the furher enquiry report of the Enquiry Officer dated 24-4-79. On perusal of Ext. M-20 and M-22 along with the Enquiry report Ext. M-21 it will appear that after the enquiry concluded on 22-2-79 and the enquiry report submitted on 27-2-79 the concerned workman had submitted to the Project Officer a copy of affidavit of Smt. Bitko Majhiain in which she was alleged to have stated that she had made allegation against the concerned workman and others on the instigation of Bajpei and others. It will appear from Ext. M-20 and M-22 that the Project Officer Tapin South directed the Enquiry Officer to take the statement of Smt. Bitko in presence of Gurudyal Singh as to whether Smt. Bitko had made any affidavit in the Court and thereafter the Enquiry Officer recorded the statement of Smt. Bitko in presence of the concerned workman on 19-4-79. Ext. M-6 is the proceeding dated 19-4-79 in which the copy of affidavit was sworn to Smt. Bitko in presence of the concerned workman and was asked whether she had gone to Hazaribagh Court to file an affidavit to which she denied. In cross-examination by the concerned workman she reiterated reported that the had not filed any affidavit or given her signature. Thus the truth of the affidavit having been filed by Smt. Bitko is belied. However, she stated on that day that the concerned workman had not committed any act (meaning thereby that she was not raped). I think the Enquiry Officer has given good reasons as to why he did not accept the said statement of Smt. Bitko. It appears that when the concerned workman was found guilty of the charge he made all efforts to win over Smt. Bitko so that he may be absolved from the charge and I think that the Enquiry Officer was correct in coming to the conclusion that Smt. Bitko was enticed and intimidated by the concerned workman and others in the filing of petition giving contradictors statement by her after the Enquiry was over on 27-2-79. The Enquiry Officer stuck to his Enquiry report dated 27-2-79 while making his further report dated 24-4-79 that the concerned workman had committed rape on Smt. Bitko.

The evidence discussed above shows that there was evidence before the Enquiry Officer to show that the concerned workman had committed rape on Smt. Bitko and good reasons have been given as to why the statement of the management's witnesses have been accepted. In view of the above evidence it cannot be said that the conclusion arrived at by the Enquiry Officer would not have been arrived. In my opinion the findings are not perverse as the same is based on evidence before the Enquiry Officer. The Enquiry Officer was careful enough to find the concerned workman guilty of the charges in respect of rape only and he has found him not guilty of the other allegations that the concerned workman had either snatched the radio or had assaulted Ratilal Manjhi or had tore of his shirt as he did not find any reliable evidence on those facts. The enquiry Officer, therefore, cannot be alleged to have any bias against the concerned workman.

In view of the above I hold that the charge of rape of Smt. Bitko by the concerned workman was established before the Enquiry Officer and I find no reasons to hold the said findings as perverse.

It has been submitted on behalf of the concerned workman that he has been doubly punished in as much as 3 annual increments with cumulative effect has been stopped and his remaining subsistence allowance of 1|3rd of his pay has been with held. The concerned workman as a way of punishment has been inflicted with the stippage of three annual increments with cummulative effect as the charge was proved against him. So far non payment of 1|3rd of his wages is concerned, the same is not stopped as a way of punishment but as the charge against the concerned workman was established the management did not think it proper to pay the remaining amount except which has been paid as subsistance allowance during the pendency of the proceeding. In accordance with clause 17(iii) of the Model Standing Order applicable in the colliery if a workman is not found guilty of the charges framed against him, he shall be deemed to be in duty during the full period of his suspension and he is entitled to receive the same wages as he would have received if he had not been suspended. This clause is applicable when a workman is found not guilty but in case a workman is found guilty of the charge it is not applicable and it is for the management to decide whether to pay the entire amount or not to the workman in case the charge have not been proved against him. The management was therefore within his rights to stop further payment for the period of suspension except the subsistance allowance which his already been paid to the concerned workman. I further hold that the non payment of amount other than subsistence allowance was not an order inflicted by way of punishment to the charge established against him.

In the result I hold that the stoppage of three annual increment of the concerned workman Shri Gurudyal Singh is legal and justified and that the action of the Project Officer, Tapin South Colliery in with holding 1|3rd of the wages of the concerned workman during his suspension period is also legal and justified. The concerned workman is not entitled to any relief.

This is my Award.

Dt. 14-8-85

I.N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012|(73)|84-D.IV(B)]

R.K. GUPTA, Desk Officer

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1985

का. आ. 4206.—भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/15/84-सी.शु.-8 तारीख 28-6-1984 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री नरेश बी. झलानी, 20 अजन्ता एपार्टमेंट्स, 10वीं मंजिल, 124/126 वाल्केश्वर रोड, बम्बई-400006 को सेन्ट्रल जेल, बम्बई में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सके जो विदेशी मुद्रा की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक हो ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और

3. अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देता है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/15/84-सी.शु.-8]

MINISTRY OF FINANCE

(Revenue Department)

ORDER

New Delhi, the 14th September, 1985

S.O. 4206.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673|15|84-Cus. VIII, dated 28-6-1984 under the said sub-section directing that Shri Naresh B. Jhalani, 20 Ajanta Apartments, 10th Floor, 124|126, Walkeshar Road, Bombay-400006 be detained and kept in Custody in the Central Prison Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing him self so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|15|84-Cus. VIII]

आदेश

का. आ. 4207.—भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/17/84-सी.शु.-8, तारीख 28-6-84 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री रविन्द्र बी झलानी, 20 अजन्ता एपार्टमेंट्स, 10वीं मंजिल, 124/126 वाल्केश्वर रोड, बंबई 400006, को सैंट्रल जेल, बंबई-400006 में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य को करने से निवारित किया जा सके जिससे विदेशी मुद्रा को संवृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता हो :

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/17/84-सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 4207.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/17/84-Cus. VIII, dated 28-6-1984 under the said sub-section directing that Shri Ravindra B. Jhalani, 20 Ajanta Apartments, 10th Floor, 124/126, Walkeshwar Road, Bombay-400006 be detained and kept in custody in the Central Prison Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/17/84-Cus. VIII]

का. आ. 4208—भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/136/84 सी. शु.-8. तारीख 29-6-84 जारी किया था जिसमें यह आदेश दिया था कि श्री जावेद खान पुत्र अली मोहम्मद खान, 4/441 कमल मैंशन, अर्थर बंदर रोड, कोलाबा, बंबई 400005 को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी को बढ़ावा देने से निवारित करने की दृष्टि से नागपुर सैंट्रल जेल नागपुर में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) ग्रेटर बंबई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/136/84-सी.शु.-8]

S.O. 4208.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/136/84-Cus. VIII, dated 29-6-1984 under the said sub-section directing that Shri Javed Khan, son of Ali Mohammed Khan of 4/441, Kamal Mansion, Arthur Bunder Road, Collaba, Bombay-400005 be detained and kept in custody in the Nagpur Central Prison, Nagpur with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Additional Commissioner of Police (Crime), Greater Bombay, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/136/84-Cus. VIII]

का. आ. 4209—भारत सरकार के अपर सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/137/84-सी०शु०-8 तारीख 29-6-84 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री सैयद मोहम्मद आरिफ बाबामिया फ्लैट नं. 10 चौथी मंजिल नसीम बिल्डिंग रेड क्रास स्ट्रीट बम्बई को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी को बढ़ावा देने से निवारित करने की दृष्टि से नागपुर सैंट्रल जेल में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है की पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (अपराध) ग्रेटर बंबई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/137/84-सी०शु०-8]

S.O. 4209.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/137/84-Cus. VIII, dated

29-6-1984 under the said sub-section directing that Shri Sayed Mohamed Arif Bawamiya Flat No. 10, 4th Floor, Naseem Building, Red Cross Street, Bombay be detained and kept in custody in the Nagpur Central Prison, Nagpur with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Additional Commissioner of Police (Crime), Greater Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|137|84-Cus. VIII]

का.आ. 4210—भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा0 सं0 673/3/187/84-सीमा शुल्क-8 तारीख 25-9-84 जारी किया गया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि श्रीरोहताश कुमार अग्रवाल उर्फ सिद्धू पुत्र श्री केदार नाथ अग्रवाल को माल की तस्करी करने तथा माल की तस्करी के लिए दुष्प्रेरित करने से उसे निवारित करने की दृष्टि से प्रेसीडेंसी जेल, अलीपुर में निरुद्ध किया जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन न हो सके।

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र प्रकाशन के सात दिन के भीतर महानिरीक्षक, पुलिस, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/187/84-सी. शु.-8]

S.O. 4210.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673|187|84-Cus. VIII, dated 25-9-1984 under the said sub-section directing that Shri Rohtas Kumar Agarwal alias Sidhu, son of Shri Kedar Nath Agarwal, be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore with a view to preventing him from smuggling goods and abetting smuggling of goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|187|84-Cus. VIII]

का.आ. 4211—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त धारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/215/84-सीमा शुल्क-8 तारीख 6-12-84 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि श्री अशोक महादेव उर्फ अशोक महतो पुत्र श्री महादेव पाटिल को माल की तस्करी और तस्करी के माल को लाने ले जाने से निवारित करने की दृष्टि से सैंट्रल जेल यरवदा, पुणे में निरुद्ध किया जाये और अभिरक्षा में रखा जाये ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे इस आदेश का निष्पादन हो सके ;

3. अत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर महानिरीक्षक पुलिस, बंबई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/215/84-सी. शु.-8]

S.O. 4211.— Whereas the Joint Secretary to the Government of India, Specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673|215|84-Cus. VIII, dated 6-12-1984 under the said sub-section directing that Shri Ashok Mahadeo Patil alias Ashok Mahato, son of Mahadeo Patil be detained and kept in custody in the Central Jail, Yerwada, Pune with a view to preventing him from smuggling goods and engaging in transporting smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|215|84-Cus. VIII]

का. आ. 4212.—भारत सरकार का संयुक्त सचिव जिसे मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974, (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/61/85-सी.शु.-8, तारीख 13-6-1985 जारी किया था जिसमें यह निदेश दिया था कि श्री निरंजन कुमार उर्फ बल्ली पुत्र श्री हकीकत राय गुलबानी सी-123, शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली को सैंट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी का माल लाने ले जाने और उसे अपने कब्जे में अपने पास रखने और तस्करी के माल को छिपाने के अलावा तस्करी के माल का धंधा करने से निवारित किया जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/61/85-सी.शु.-8]
आर. के. तिवारी, उप सचिव

S.O. 4212.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foregin Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/61/85-Cus. VIII, dated 13-6-1985 under the said sub-section directing that Shri Niranjan Kumar alias Balli, son of Shri Hakikat Rai Gulabani, C-123, Shakti Nagar Extension, Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in transporting and keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by concealing smuggled goods;

2. Whereas the Central Governmeent has reason be believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/61/85-Cus. VIII]
R. K. TIWARI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985